DD
दिव्य दिल्ली
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र
RNI No. DLHIN/25/A2321
वर्षः 01, अंकः 17, पृष्ठः 08
infodivyadelhi@gmail.com
बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi
तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री | सूर्योदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअपः शाह

देश में आज 1.92 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक

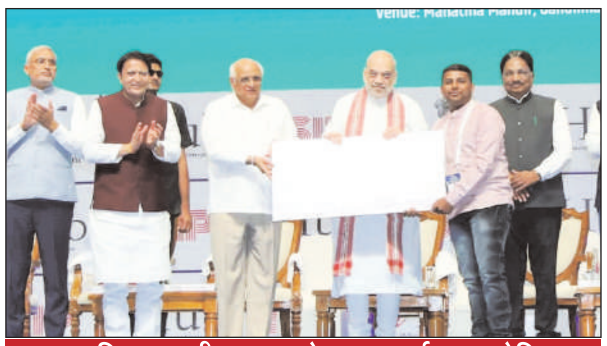

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल इकोसिस्टम बन गयाः अमित शाह

गांधीनगर
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2025 का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के माइंड टू मार्केट के विचार को साकार करने का मंच साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पिछले एक दशक में स्टार्टअप्स की संख्या में 380 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर के साथ आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित दो दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव और एग्जिबिशन-2025 का आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में शुभारंभ के बाद विभिन्न स्टार्टअप स्टॉल्स का अवलोकन कर उद्यमियों से संवाद किया। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया। देश के युवा उद्यमियों को स्टार्टअप क्षेत्र में आई क्रांति का श्रेय देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 500 के आसपास स्टार्टअप्स और मात्र चार यूनिकॉर्न थे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं में छिपी क्षमताओं को सामने लाने के लिए कि गए प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप आज देश में 1.92 लाख से भी अधिक स्टार्टअप्स और 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न सक्रिय हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक है।

भारत का युवा जॉब गीवर बन रहा

आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब गीवर बन रहा है। उन्होंने निवेशकों और उद्योगपतियों से युवाओं की इस क्षमता का लाभ उठाने की भी अपील की। स्टार्टअप कॉन्क्लेव के इस दूसरे संस्करण के बारे में उन्होंने कहा कि लगातार दो दिन चलने वाले इस कॉन्क्लेव में भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने और हर नागरिक के जीवन में समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए चिंतन और विचार-विमर्श के जरिए सात सत्रों में समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। वर्ष

2023 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की सफलता के बाद यह दूसरा संस्करण देश और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में और अधिक सहायक सिद्ध होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 91वें स्थान पर था।

400 वृक्षों का किया गया रोपण

गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर शहर में ग्रीनफील्ड का विस्तार बढ़ाने के लिए "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" के अंतर्गत गांधीनगर के सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वावोल-उवारसद रोड पर वृक्षारोपण किया गया। गांधीनगर महानगरपालिका के जन संपर्क विभाग ने बताया कि गांधीनगर के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए गांधीनगर महानगरपालिका और इफको के संयुक्त उपक्रम से वावोल-उवारसद रोड पर स्थित श्री हरि 142 प्लॉट के पास लगभग 400 वृक्षों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने वटवृक्ष का रोपण किया। साथ ही इफको द्वारा जिले के विभिन्न 11 ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर मीराबेन पटेल, विधायक रीटाबेन पटेल, विधायक अल्पेशभाई मौजूद रहे।

शनि शिंगणापुर देवस्थान ट्रस्ट बोर्ड भंग; कलेक्टर को सौंपी कमान

अहिल्यानगर
महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर स्थित शनैश्वर मंदिर ट्रस्ट बोर्ड को भंग कर दिया गया है। पिछले काफी समय से मंदिर ट्रस्ट पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसपर एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने ट्रस्ट बोर्ड को ही भंग कर दिया। शनि शिंगणापुर देवस्थान ट्रस्ट पर मंदिर का मैनेजमेंट सही तरह न करने, वित्तीय कुप्रबंधन और फर्जी ऐप के जरिए श्रद्धालुओं से पैसा वसूलने का आरोप लग रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने ट्रस्ट भंग करते हुए मंदिर का पूरा दारोमदार जिला कलेक्टर को सौंप दिया है।

जिला कलेक्टर पर जिम्मेदारी
महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के अनुसार, फिलहाल के लिए मंदिर का प्रशासन जिला कलेक्टर के हाथों में रहेगा। मंदिर की अचल संपत्ति से लेकर श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं का ध्यान रखना और धार्मिक कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। बता दें कि शनि शिंगणापुर में स्थित शनैश्वर मंदिर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। हालांकि, पिछले काफी समय से मंदिर से ढेर सारी शिकायतें आ रही थीं। इसके लिए सरकार ने जांच शुरू करवाई थी।

जांच के बाद सरकार ने लिया फैसला
जांच पूरी होने के बाद राज्य सरकार ने ट्रस्ट को भंग करने का फैसला किया। सरकार ने भक्तों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए जिला कलेक्टर को मंदिर का जिम्मा सौंप दिया है। सरकार ने मंदिर में पारदर्शिता लाने और वित्तीय लेन-देन में सुधार के आदेश दिए हैं।

शराब घोटाले में 28 अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपित बनाए गए 28 अधिकारी आज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की विशेष अदालत में पेश हुए। न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक सभी अधिकारी अग्रिम जमानत के कागजात लेकर जमानतदारों के साथ अदालत पहुंचे थे।

विदेश नीति अब रीढ़ की हड्डी हैः शाह

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तुलना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस की बाद की सरकारों से की। शाह ने कहा, "जब इतिहासकार मोदी के युग की तुलना अन्य प्रधानमंत्रियों के युग से करेंगे तो परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में होगा।" उन्होंने कहा, "एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अनुच्छेद

370, राम मंदिर, तीन तलाक, देश की नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट करना, पूरे देश में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ाना, ये सब सिर्फ एक दशक में हुआ है।"

'भारत की विदेश नीति में मजबूती पीएम मोदी लेकर आए'
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में मजबूती लाने का काम किया है, जिसका पहले अभाव था। गृह मंत्री ने कहा, "भारत की विदेश नीति का गहन अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी की कमी थी। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति में रीढ़ जोड़ने का काम किया है।"

पीएम मोदी को लेकर अमित शाह ने और क्या कहा?
उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि वह हर भूमिका में खुद को सफलतापूर्वक ढाल लेते हैं।

अंसल भाइयों के 60 करोड़ से बने ट्रॉमा सेंटर्स की जांच करें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उपहार सिनेमा अग्निकांड पीड़ित संघ (एवीयूटी) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली सरकार द्वारा बताए गए उन ट्रॉमा सेंटर्स का दौरा करे, जिनके निर्माण के लिए अंसल बंधुओं द्वारा जमा कराए गए 60 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। अदालत ने कहा कि अगर इन केंद्रों में किसी सुविधा की कमी पाई जाती है, तो सुधार के लिए आवश्यक आदेश दिए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, उज्जल भुयान और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने एवीयूटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता से कहा कि वे किसी प्रतिनिधि को भेजकर इन अस्पतालों की हकीकत जानें।

जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद बाजार में उमड़ी भीड़

नए जीएसटी नियमों के लागू होने के बाद खरीदारों की भीड़ उमड़ी खुदरा विक्रेताओं ने आकर्षक छूट दी

नई दिल्ली
नवरात्र के पहले दिन जीएसटी बचत उत्सव पर सोमवार को बाजार में धूम दिखाई दी। नया जीएसटी नियम लागू होने के बाद बाजार में खरीदार उमड़ पड़े। खुदरा विक्रेताओं ने आकर्षक छूट की पेशकश की, जिसके चलते खरीदारों में जोश देखा गया। एयर कंडीशनर और टेलीविजन से लेकर कारों की बिक्री में जोरदार उछाल देखा गया। एसी और टीवी की बिक्री में 30-35 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई। इसी तरह कारों की बिक्री में देशभर में जबर्दस्त वृद्धि हुई।

एनसीआर में हुई सबसे ज्यादा वाहनों की बिक्री
नया जीएसटी नियम लागू होने के साथ नवरात्र का भी पहला दिन होने से वाहन खरीद के लिए जबर्दस्त रुझान देखा गया। देश की सबसे बड़ी कार निमार्ता कंपनी मारुति सुजुकी ने 25 हजार कारों की डिलीवरी की। हुंडई ने 11 हजार कारें डीलरों को बेचीं। एनसीआर में वाहनों की सबसे अधिक बिक्री हुई, जिसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई का स्थान रहा। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों चार स्लैब वाली कर प्रणाली को खत्म कर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब वाली प्रणाली को मंजूरी दी थी। इससे घी, पनीर, मक्खन, सूखे मेवे, काफी आदि

एसी और टीवी की बिक्री में 30-35 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई

रोजमर्रा के जरूरी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और मेडिकल उपकरण समेत 295 आइटम सस्ते हो गए। टीवी, एसी, दोपहिया वाहन आदि की कीमतें भी कम हो गईं। कुल 453 आइटमों पर जीएसटी दरें कम की गई हैं। छोटी कारों पर 18 प्रतिशत और बड़ी कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी की गई है।

कार कंपनियों ने क्या कहा?
मारुति सुजुकी ने कहा है कि जीएसटी कटौती के पहले दिन उसने 25 हजार कारों की डिलिवरी की। कंपनी ने कहा कि ऐसी ही मांग रही तो उसके कई माडलों के स्टाक खत्म हो जाएंगे। हुंडई ने 11 हजार कारों की डिलिवरी डीलरों को की, जो पिछले पांच सालों में किसी भी एक दिन में उसकी तरफ से डीलरों को भेजे गए सबसे अधिक वाहन हैं।

सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया जब्त

नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी कंपनियों के 7.44 करोड़ रुपये की अचल-संपत्तियों को जब्त कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 7.44 करोड़

रुपये की अचल-संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की है। ईडी के मुताबिक इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 12.25 करोड़ रुपये है।

आधुनिक युद्धः एकीकृत तकनीकी समाधानों की जरूरतः सीडीएस चौहान

नई दिल्ली
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि आधुनिक युद्ध की निरंतर बदलती प्रकृति से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत और एकीकृत तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है।
वह यहां तीनों सेनाओं की एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु सेना-अकादमिक अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में

समन्वय स्थापित करना है।

बताया कैसे विकसित होंगी स्वदेशी क्षमताएं
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने भविष्य की परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों, हथियारों, नेटवर्कों में सिद्धांतों और स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने में शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप और उद्योग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण अपनाने का भी आह्वान किया और शिक्षाविदों से नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को "अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। संबोधन में सीडीएस ने आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला।

भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों के लिए जारी रहेगी "नो एंट्री"

नई दिल्ली
भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद रखने की समयसीमा को फिर से बढ़ा दिया गया है। पड़ोसी मुल्क के सैन्य या नागरिक विमान 24 अक्टूबर तक भारत के एयरस्पेस में एंट्री नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस 24 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा कर दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया था, जिसके बाद में पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद रखने का एलान कर दिया था।

भारत और पाकिस्तान ने अलग-अलग नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसमें एयरस्पेस बंद रखने का आदेश दिया गया है। भारत के द्वारा आज जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, सैन्य विमान समेत कोई भी पाकिस्तानी रजिस्टर एयरक्राफ्ट या पाकिस्तानी एयरलाइंस के द्वारा खरीदा और लीज पर लिए गए किसी भी एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरस्पेस में एंट्री नहीं मिलेगी। 23 अक्टूबर की रात 11:59 बजे तक पाकिस्तान के सभी विमानों के लिए भारतीय एयरस्पेस पूरी तरह से बंद रहेगा।

30 अप्रैल से बंद है एयरस्पेस
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। ऐसे में भारत ने पाक विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने की घोषणा कर दी थी। यह आदेश 30 अप्रैल से लागू हो गया था। इसके बाद से समयसीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में उपज खरीदी के लिए केंद्र ने दी मंजूरी

नई दिल्ली
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति दी है। इसके साथ किसानों से उड़द व तूर की शत-प्रतिशत खरीद के लिए मंत्रालय ने मंजूरी दी है, वहीं उत्तर प्रदेश में मूंग, तिल, मूंगफली तथा गुजरात में सोयाबीन, मूंग व मूंगफली भी खरीदने की अनुमति प्रदान की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअल बैठक में उप्र के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही तथा गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल शामिल थे।
वहीं केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी तथा केंद्र व दोनों राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल व सुचारू रूप से की जाएं, जिस पर दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कहा कि उपज खरीद आधुनिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व पीओएस मशीन व्यवस्था के साथ डिजिटल पोर्टलों के जरिए होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद शिवराज सिंह ने राज्य में उड़द 2

लाख 27 हजार 860 मीट्रिक टन (100 प्रतिशत) खरीद को स्वीकृति प्रदान की, जिसका मूल्य 1777.30 करोड़ रुपये रहेगा। तूर की भी शत-प्रतिशत 1,13,780 मीट्रिक टन खरीद के लिए केंद्र की ओर से शिवराज ने मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 910.24 करोड़ रु. रहेगी। मूंग की 1983 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी कीमत 17.38 करोड़ रु. होगी। इसके अलावा, तिल की 30,410 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 299.42 करोड़ रु. होगी। साथ ही मूंगफली की 99,438 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसका मूल्य 722.22 करोड़ रु. रहेगा। शिवराज सिंह ने गुजरात में किसानों के लिए उड़द की पूरी 47,780 मीट्रिक टन उपज की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 372.68 करोड़ रु. होगी।

साथ ही, सोयाबीन की 1,09,905 मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 585.57 करोड़ रु. होगी। गुजरात में मूंगफली की 12 लाख 62 हजार 163 मीट्रिक टन मात्रा खरीदने की स्वीकृति केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 9,167.08 करोड़ रु. रहेगी। इसके अलावा, मूंग 4,415 मीट्रिक टन खरीदने की स्वीकृति शिवराज सिंह ने दी है। जिसका मूल्य 38.71 करोड़ रु. रहेगा।

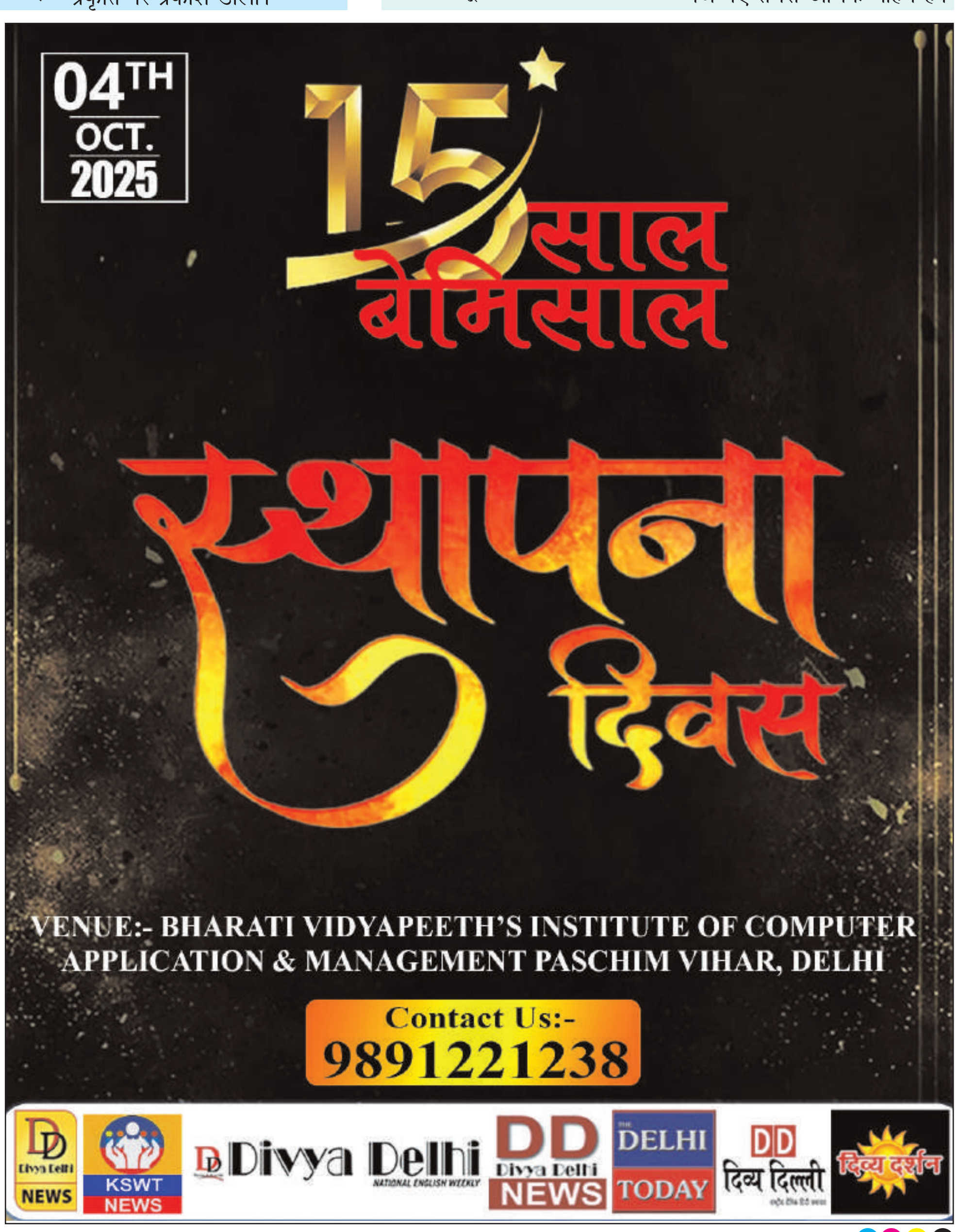

जीएसटीः अब दुकानदारों और कंपनियों पर होगा एक्शन

जीएसटी दरों में कटौती के बाद ग्राहकों तक इसका लाभ पहुँचाना सरकार के लिए एक चुनौती

नई दिल्ली
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में व्यापक कटौती के लागू होने के बाद सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों तक इसका लाभ पहुंचाने की है। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय स्तर पर निगरानी तंत्र बनाया गया है। उपभोक्ताओं की ओर से ब्रांड कंपनियों के खिलाफ शिकायत आने पर इसे अनुचित प्रथा मानते हुए क्लास एक्शन (सामूहिक कार्रवाई) लिया जाएगा। खुदरा बाजार में पूर्व से पैक उत्पादों के मूल्य में कटौती नहीं करने की शिकायतें आने के बाद सरकार ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि उनकी सारी शिकायतें सुनी जाएंगी और उन पर तत्परता से कार्रवाई भी होगी। अगर कोई दुकानदार नई दरों पर सामान नहीं देता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत करें। हालांकि सरकार ने उद्योग जगत की समस्याओं का भी ख्याल रखा है और मौजूदा स्टाक पर नया एमआरपी लगाने को थोड़ा लचीला बनाया है।

नया स्टीकर लगाना संभव नहीं
संशोधित कीमतों के साथ पुरानी पैक का उपयोग मार्च 2026 तक किया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने स्वीकार किया कि कई उत्पाद पहले से बाजार की सप्लाई चेन में हैं और उन पर नया स्टिकर लगाना संभव नहीं है। इसे स्वैच्छिक किया गया है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिले। पहले से पैक उत्पादों पर नई दरों का लाभ देना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कंपनियों और वितरकों को उठाना ही पड़ेगी। संशोधित दरें लागू करने के पहले सरकार के स्तर पर दो-दो बार बैठक कर सबको सख्त चेतावनी दी जा चुकी है। फिर भी यदि कंपनियां और विक्रेता ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले दिन की उपलब्धि से उत्साहित निधि खरे ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्राहकों से शिकायतें आ रही हैं। साथ ही सलाह-सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। सरकार ने निमार्ताओं, पैकर्स और आयातकों को अनुमति दी है कि वे उपभोक्ताओं को संशोधित एमआरपी की जानकारी स्वेच्छा से प्रदान करें। यह जानकारी डिजिटल माध्यमों, तुलनात्मक दर चार्ट या अन्य नवाचारी तरीकों से दी जा सकती है।

जीएसटीः नेस्ले इंडिया ने कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की घोषणा की

शिमला
नेस्ले इंडिया ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) दरों में बदलाव का स्वागत किया है। कंपनी ने कहा है कि 22 सितंबर 2025 से यह लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाएगा। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष तिवारी ने कहा जीएसटी दर में कटौती भारत के उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। नेस्ले पिछले 113 वर्षों से भारत का अभिन्न हिस्सा रही है और हमारे लिए उपभोक्ता हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं।

जीएसटीः संचार माध्यमों से लोगों को करें जागरूक

कंपनियों को हिदायत दी गई है कि नई जीएसटी दरों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विज्ञापनों, मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है।

कैसे करें शिकायत?
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी की नई दरें लागू कराने की जिम्मेवारी निमार्ता कंपनियों की है। अगर किसी कंपनी का कोई उत्पाद पूर्व में प्रिंट कीमत से कम पर ग्राहकों को नहीं दिया जा रहा है और खुदरा दुकानदार किसी तरह के बहाने कर रहा है तो प्रमाण के तौर पर उसकी आवाज को रिकार्ड कर शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री नंबर 1915 के अतिरिक्त वॉट्सएप, मोबाइल एप्स और ई-पोर्टल की भी सुविधा है। हाल ही में मंत्रालय ने इनग्राम पोर्टल पर जीएसटी के लिए अलग कैटेगरी बना दी है, ताकि इस तरह की शिकायतें जल्दी और प्रभावी तरीके से निपटाई जा सकें। ग्राहक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

जीएसटी नियमों में हुए बदलाव की व्यापारियों को दी जानकारी

मथुरा
केन्द्र सरकार द्वारा देश के व्यापारियों के हित में लिए गए फैसले के अंतर्गत जीएसटी सरलीकरण को लेकर मथुरा जनपद के सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी की एक बैठक जॉइंट कमिश्नर जीएसटी रमेश सिंह की अध्यक्षता में राजीव भवन स्थित कार्यालय पर हुई।

बैठक में जीएसटी को लेकर सभी व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापारियों के हित में जीएसटी सरलीकरण किया जाने को लेकर सभी ने हर्ष ध्वनि से मोदी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जनपद के प्रमुख व्यापारी नेता शिव शंकर वर्मा ने अपने पुराने संस्मरण सुनाते हुए व्यापारियों में जोश भरा तो वही जॉइंट कमिश्नर व्यापार कर रमेश सिंह से आग्रह किया कि जनपद में बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न पर तुरंत रोक लगाई जाए वही उन्होंने कहा कि जनपद का व्यापारी सदैव एक जो ठोकर आपके विभाग के साथ कम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। वशर्ते विभाग भी व्यापारियों के प्रति अपना नरम रुख रखें और उनको जीएसटी सरलीकरण के अनुरूप समय समय पर परामर्श भी दे। वही इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जीएसटी प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी कमल किशोर वार्ष्णेय ने जीएसटी सारणीकरण में कमियां बताते हुए बताया कि अभी भी बड़े व्यापारी जीएसटी स्लैब में हुए सरलीकरण को नहीं मानकर 12 पर्सेंट टैक्स ले रहे हैं जबकि सरकार द्वारा जीएसटी टैक्स अब मात्र 18 प्रतिशत व 5 प्रतिशत ही होगा।

महिला केन्द्रित विकास का मॉडल बनाने वाली योजना महतारी सदनः मुख्यमंत्री साय

धमतरी/रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गांव से छत्तीसगढ़ के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ को महिला-केंद्रित विकास का मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नवरात्र के पावन पर्व के दौरान शुरू की गई महतारी सदन योजना को मुख्यमंत्री ने प्रदेश की माताओं और बहनों की तरक्की के लिए सशक्त और कारगर कदम बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि माताओं-बहनों, के लिए गाँवों में ही केंद्र बनाने महतारी सदनों के निर्माण की घोषणा सरकार ने की थी ताकि आप वहां एकत्रित हो कर एक बड़ी सुविधापूर्ण जगह में मिल-जुलकर अपना काम कर सकें। आज यह बड़ा काम पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि महतारी सदन केवल महिलाओं की तरक्की का आधार ही नहीं बनेगा, बल्कि यह पूरे प्रदेश की तरक्की का आधार बनेगा। यह महतारी सदन माताओं-बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र होगा। महतारी सदन शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि इन सदनों में महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। माताएँ-बहनों के लिए महतारी सदन में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आस्था महिला संकुल संगठन करेली बड़ी की महिला समूह सदस्यों को महतारी सदन का हस्तांतरण प्रमाण पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने परिसर मौलश्री का पौधा भी रोपा।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी, पूर्व मंत्री एवं कुरूद के विधायक अजय चन्द्राकर सहित सचिव निहारिका बारिक और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं गणमान्य नौगरिक मौजूद रहे।

टिप्पणीझः अदालतें वसूली के लिए रिकवरी एजेंट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को रिकवरी एजेंट की तरह काम करने से सख्त मना किया है। कोर्ट का कहना है कि दीवानी मामलों को आपराधिक केस में बदलने की प्रक्रिया कम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे वसूलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने का ट्रेंड आजकल आम हो गया है। पैसे की रिकवरी के लिए कई लोग आपराधिक मामले दर्ज करवा देते हैं, जबकि यह एक दीवानी मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई उत्तर प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों के संदर्भ में की थी। एक मामले में पैसे की वसूली के लिए व्यक्ति के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज कर दिया गया था। यूपी सरकार ने बताई पुलिस की दुविधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस बीच में फंस जाती है।

अगर दीवानी मामलों में पुलिस केस दर्ज नहीं करती है, तो अदालत से फटकार सुनने को मिलती है और अगर केस दर्ज होता है, तो इसे पक्षपात और कानून के खिलाफ बताया जाता है।

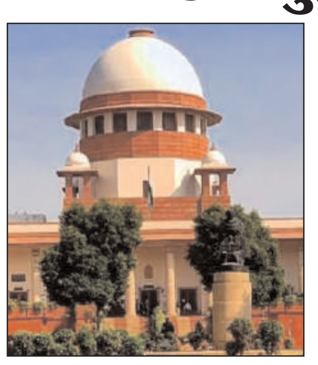

नक्सल समूहों में हथियार डालने पर मची रार

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश के सभी हिस्सों से 'नक्सलवाद' को पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़, झारखंड व तेलंगाना और ओडिशा सहित अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ एवं दूसरे सुरक्षा बल, नक्सलियों पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। नक्सलियों के शीर्ष कमांडर, जिन पर करोड़ों रुपये का इनाम रखा गया है, वे मारे जा रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नक्सलियों के खात्मे की डेड लाइन करीब आ रही है और इस बीच एक नया घटनाक्रम देखने को मिला है। नक्सल समूहों में हथियार डालने को लेकर रार मच गई है। 15 अगस्त को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित की बात कही। इसके बाद कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ तो अब 20 सितंबर को केंद्रीय कमेटी की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि दुश्मन को हथियार सौंप कर, मुख्यधारा में शामिल होना यानी पीड़ित जनता के साथ विश्वासघात करना, ये हमारी नीति नहीं है। माओवादियों की ताजा अपील में नेपाल का भीषण विरोध प्रदर्शन, जिसे क्रांति का नाम दिया गया, का जिक्र हुआ है। बता दें कि 15 अगस्त को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने केंद्रीय गृह मंत्री एवं नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम एक अपील जारी की थी। इसमें शांति वार्ता की बात कही गई। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिया गया। दूसरी तरफ सरकार ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। खुफिया इनपुट में यह बात सामने आई कि खात्मे की डेड लाइन करीब देख नक्सली अब भागने के रास्ते तलाश रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने 'आईईडी' को अपना अंतिम हथियार बनाया है।

वंदे भारतः अब सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली से पहुंचे जोधपुर...

मंगलवार को छोड़ सप्ताह में छह दिन चलेगी ट्रेन

जोधपुर से प्रारंभ होने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन

नई दिल्ली
रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 27 सितंबर से संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। जोधपुर मंडल से चलने वाली दूसरी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर रेल यात्रियों में बड़ा उत्साह है,ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन 26481,जोधपुर-दिल्ली कैंट-वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर)जोधपुर से सुबह 5.25 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 दिल्ली कैंट पहुंचेगी।इसी प्रकार ट्रेन 26482, दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) 27 सितंबर से दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर उसी दिन रात्रि 11.20 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी।

आवागमन में इन आठ स्टेशनों पर ठहराव
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवागमन में मेड़ता रोड, डेगाना,मकराना,फुलेरा,जयपुर,अलवर,रेवाड़ी और गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जिसमें सात वातानुकूलित कुसीर्यान व एक एग्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुसीर्यान श्रेणी के डिब्बे होंगे।

दो साल बाद जोधपुर वासियों को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर मंडल की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। इससे पहले जोधपुर से साबरमती स्टेशनों के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई 2023 से चलना प्रारंभ हुई थी।

सुदर्शन चक्र होगा सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टमः एयर मार्शल दीक्षित

नई दिल्ली
भारत अपने रक्षा कवच को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़े कदम की ओर बढ़ रहा है। प्रस्तावित एयर डिफेंस सिस्टम ह्यसुदर्शन चक्रह्ल आने वाले समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और व्यापक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। यह प्रणाली ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईएससी) एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि यह प्रणाली बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगी। वे काउंटर यूएवीज एंड एयर डिफेंस सिस्टम्सः फ्यूचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दीक्षित ने बताया कि मिशन सुदर्शन चक्र में काउंटर-ड्रोन, काउंटर-यूएवी और काउंटर-हाइपरसोनिक क्षमताओं को एकीकृत किया जाएगा।

युद्ध का नया स्वरूप
एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि युद्ध अब शतरंज की तरह है, जिसमें दुश्मन से दो कदम आगे रहना जरूरी है। उन्होंने अजरबैजान-अर्मेनिया संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे सस्ते ड्रोन महंगे सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

एआई और तकनीकी चुनौतियां
दीक्षित ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जिसमें पकड़े गए ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस थे। उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाइयों में एआई आधारित हथियार बड़ी चुनौती होंगे।

मराठवाड़ा में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ से फसलें बर्बाद, आठ की मौत

नई दिल्ली
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले चार दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। इस आफत की वजह से आठ लोगों की मौत हो गई। जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान और हजारों हेक्टेयर फसलों की बबार्दी भी हुई है। धाराशिव जिले में बाढ़ जैसे हालात में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और नावों की मदद ली गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रभावितों को त्वरित राहत का भरोसा दिलाया है। 20 सितंबर से मराठवाड़ा के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इससे बांधों का जलस्तर बढ़ गया और पानी छोड़ना पड़ा। इस दौरान लातूर में तीन, बीड में दो और छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, धाराशिव में एक-एक व्यक्ति की मौत बिजली गिरने, डूबने और अन्य कारणों से हुई। धाराशिव में 159 गांव प्रभावित हुए, जहां 766 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए और पांच झोपड़ियां पूरी तरह नष्ट हो गईं।

कोलकाता में बारिश ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड, ट्रेन-मेट्रो और विमान सेवा प्रभावित

कोलकाता
कोलकाता व आसपास के जिलों में सोमवार रात से लेकर मंगलवार सुबह तक हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। जलजमाव में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से सात लोगों की मौत हो गई। कोलकाता और हावड़ा में कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे सड़क, ट्रेन यहां तक कि मेट्रो सेवा भी ठप हो गई। क्रू मेंबर और पायलटो के देर से पहुंचने से विमान सेवा भी प्रभावित हुई है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के मुताबिक पिछले चार दशक में सितंबर महीने में अब तक की सबसे ज्यादा 300 मिलीमीटर बारिश हुई है।

शहर में और अधिक बारिश होने की आशंका
कोलकाता के कई इलाके जलमग्न हैं। हावड़ा के रेलवे यार्ड में भी बारिश का पानी घुस गया है। बारिश का पूजा पंडालों की तैयारियों पर भी भारी असर पड़ा है। आधी रात के बाद लगातार पांच घंटे हुई भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कोलकाता में कई घरों एवं आवासीय परिसरों में पानी घुस गया। शहर में और अधिक बारिश होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अनुसार, शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता ज्यादा रही। गड़िया में कुछ ही घंटों में 332 मिलीमीटर बारिश हुयी, जबकि जोधपुर पार्क में 285 मिमी बारिश दर्ज की गई। कालीघाट में 280 मिमी, तपसिया में 275 मिमी, बालीगंज में 264 मिमी, जबकि उत्तर कोलकाता के कुछ इलाकों में 195 मिमी बारिश हुई।

बंगाल की खाड़ी में एक और नया लो प्रेशर प्वाइंट बनने की संभावना
आइएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरपूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बुधवार तक दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

आत्मनिर्भर भारत-हरियाणा की परिकल्पना को साकार करेगी नई जीएसटी व्यवस्थाः कृष्ण पंवार

जींद
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जीएसटी पर घटोत्तरी लागू कर एक नया आयाम स्थापित किया है। इस व्यवस्था से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा की परिकल्पना साकार होगी। नई जीएसटी व्यवस्था से गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों, व्यापारियों सहित सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी पर घटोतरी लागू कर देशवासियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार मंगलवार को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स और जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय हीरो एजेंसी, महिंद्रा, बजाज तथा स्वराज एजेंसियों में जाकर वाहन खरीद रहे उपभोक्ताओं से बातचीत की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी की नई व्यवस्था लागू हो गई है। इस व्यवस्था से कारोबार को और आसान व निवेश को और आकर्षक बना सकते हैं। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और राज्य के प्रयासों का परिणाम है कि देश दर्जनों करों के जाल से मुक्त हुआ है और एक राष्ट्र-एक कर का सपना साकार हुआ है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का ख्याल रखा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा-2025 के दौरान दिल्ली और बड़ौत के बीच नई एसी बस सेवा शुरू की गई

दिल्ली-बड़ौत के लिए एसी बस सेवा शुरू

सभी वर्गों के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बेहद ही किफायती किराया निर्धारित किया है

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा-2025 के दौरान मंगलवार को राजधानी में दिल्ली और बड़ौत के बीच नई एसी बस सेवा की शुरूआत की गई। बसों की कमी के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने तीन बसों को महाराणा प्रताप आईएसबीटी से हरी झंडी दिखाई। इन बसों पर केसरिया रंग का भी प्रयोग किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई अंतरराज्यीय एसी बस सेवा से दिल्ली और यूपी के बस यात्रियों और विशेषकर छात्रों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

न्यूनतम किराया 32 रुपये, अधिकतम 125 रुपये निर्धारित

प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली और बड़ौत के बीच नई एसी बस सेवा शुरू की जाएगी। यह बस दिल्ली के महाराणा प्रताप आईएसबीटी से बड़ौत तक चलेगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। न्यूनतम किराया 32 रुपये और अधिकतम 125 रुपये निर्धारित किया गया है। बसें सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध रहेंगी जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दिल्ली सरकार के अनुसार नई बस सेवा दिल्ली के महाराणा प्रताप आइएसबीटी से शुरू होकर खजूरी खास, भजनपुरा, लोनी बस स्टैंड, यूपी बार्डर, लोनी, मंडोला, खेकरा, काठा, बागपत, गौरीपुर, सरूरपुर और ट्योढ़ी से होते हुए बड़ौत तक पहुंचेगी।

इन जगहों से होकर गुजरेगी बस

ठीक इसी तरह बड़ौत से दिल्ली आने वाली एसी बसें ट्योढ़ी, सरूरपुर, गौरीपुर, बागपत, काठा, खेकरा, मंडोला, लोनी, लोनी बस स्टैंड/यूपी बार्डर, भजनपुरा और खजूरी खास से होते हुए महाराणा प्रताप आईएसबीटी तक आएंगी।

ये बसें रोजाना सुबह 4 बजकर 50 मिनट, 5 बजकर 20 मिनट और 5 बजकर 50 मिनट पर शुरू होकर दिल्ली से बड़ौत तक जाएंगी। तो वहीं यूपी के बड़ौत बस डिपो से दिल्ली की तरफ सुबह 7:00 बजे, 7 बजकर 30 मिनट और 8:00 बजे बसें रवाना होंगी।

शाम के समय पर एक नजर

खासकर शाम के समय बस कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी। दिल्ली से बड़ौत की ओर शाम 5:00 बजे, 5:30 बजे और 6:00 बजे एसी बसें चलेंगी, जबकि बड़ौत से दिल्ली की तरफ 7:30 बजे, 8:00 बजे और 8:30 बजे बसें रवाना होंगी।

रामलीला उत्सव समाज को एकजुट कर सांस्कृतिक धरोहर को सुदृढ़ करता है : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को विभिन्न रामलीला आयोजनों में सम्मिलित होकर भगवान श्रीराम की आराधना की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलीला उत्सव न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज को एकजुट कर सांस्कृतिक धरोहर को भी सुदृढ़ करता है। विजेंद्र गुप्ता ने लाल किला मैदान में आयोजित नव श्री धार्मिक लीला में गणेश वंदना में की। परेड ग्राउंड में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इसे भगवान श्रीराम के आदर्शों और मर्यादा का सजीव चित्रण बताया।

उन्होंने कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं, बल्कि यह हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की याद दिलाती है कि हमें सदैव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।

सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्धः रेखा

नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि उनकी सरकार ने सांस्कृतिक आयोजनों जैसे रामलीला और दुर्गा पूजा को रात 12 बजे तक आयोजित करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रामराज्य आना चाहिए और इसके लिए "हम सभी को थोड़ा प्रयास करना होगा।"

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये आयोजन समाज में एकता और सौहार्द को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, "रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। इनके माध्यम से हम अपनी परंपराओं को जीवित रख सकते हैं और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ सकते हैं।" गुप्ता ने बताया कि सरकार ने आयोजकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि इन आयोजनों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लें, लेकिन नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि रामराज्य का मतलब है न्याय, समानता और शांति। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और जनता का सहयोग इसमें महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार और जनता को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से एकजुट होकर रामराज्य के सपने को साकार करने का आह्वान किया।

चित्रकार संजय कुमार गिरि को मिलेगा राष्ट्रीय विभूति सम्मान

नई दिल्ली

करतार नगर, दिल्ली में रहने वाले कवि पत्रकार एवं चित्रकार संजय कुमार गिरि को राष्ट्रीय विभूति सम्मान-2025 के लिए चयनित किया गया हैं। यह सम्मान श्री गिरि को योगेश शिक्षा कला, संस्कृति एवं पर्यावरण उत्थान ट्रस्ट के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान संजय को उनकी चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया जाएगा। संजय ने हिंदुस्तान के लगभग 300 से साहित्यकारों एवं कवियों फिल्मस्टारों के पेन्सिल स्केच बना कर उन्हें भेंट कर चुके हैं। जिनमे पद्म अशोक चक्रधर, हरिओम पवार, अरुण जैमिनी, डॉ विष्णु सक्सेना, कवि दीपक गुप्ता, आचार्य ओम नीरव, लव कुमार 'प्रणय' प्रो विश्वम्भर शुक्ल आदि साहित्यकार प्रमुख हैं। हाल ही में इसी पर उनकी एक पुस्तक *चित्रमंथन भी प्रकाशित होने जा रही हैं. श्री गिरि कि कविताओं कि अभी तक लगभग 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं इनकी एक पुस्तक तुमको अपनी जीत लिखूं जो शब्दाकुर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई हैं।

सेवा पखवाड़ा के तहत राजधानी के 71 स्थानों पर चला सफाई अभियान

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के अवसर पर दिल्ली में मंगलवार को बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली सरकार और भाजपा नेताओं की अगुवाई में राजधानी के 71 स्थानों पर फ्लाईओवरों और आसपास के इलाकों में सफाई की गई। इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद, विधायक, निगम पार्षद, दिल्ली सरकार के मंत्री और बड़ी संख्या में कार्यकताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा के रिंग रोड क्षेत्र में सफाई अभियान का नेतृत्व किया। उनके साथ मंत्री रविंद्र इन्द्रराज सिंह और निगम उपमहापौर जय भगवान यादव भी शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सफाई सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम न होकर रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए, तभी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आईटीओ फ्लाईओवर और रोज गार्डन क्षेत्र में अभियान की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां देश के कोने-कोने से लोग रहते हैं। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास सफाई बनाए रखे।

राजधानी के विभिन्न इलाकों में भाजपा नेताओं ने अलग-अलग स्थानों पर सफाई अभियान चलाया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोहे के पुल पर, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आर के पुरम में, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सराय काले खान फ्लाईओवर के नीचे, सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आईएसबीटी कश्मीरी गेट से चंदगी राम अखाड़ा तक, सांसद कमलजीत सहरावत ने नारायणा फ्लाईओवर और भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने सफदरजंग एनक्लेव और सरोजिनी नगर क्षेत्रों में सफाई कार्य का नेतृत्व किया।

विधायक सतीश उपाध्याय ने एम्स फ्लाईओवर, राजकुमार भाटिया ने आजादपुर फ्लाईओवर, शिखा राय ने मूलचंद साउथ एक्सटेंशन, कैलाश गहलोत ने मोतीबाग गुरुद्वारा, गजेन्द्र यादव ने एम्स परिसर, अशोक गोयल ने मॉडल टाउन और अभय वर्मा ने आईटीओ क्लोवरलीफ फ्लाईओवर पर सफाई अभियान का नेतृत्व किया।

दो करोड़ की एमडीएमए बरामद, विदेशी नागरिक सहित दो गिरफ्तार

नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 202 ग्राम एमडीएमए (एक्स्टसी) और इंजेक्शन-सिरिंज जब्त की हैं। बरामद नशीले पदार्थों की कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने एक भारतीय और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में ड्रग सप्लायरों का गिरोह सक्रिय है। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। रात करीब 12:10 बजे चिराग दिल्ली इलाके में एक संदिग्ध कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार से 196 ग्राम एमडीएमए (एक्स्टसी), चार इंजेक्शन और आठ सिरिंज बरामद किए गए। मौके पर आरोपित गोविंदपुरी निवासी आकाश कश्यप उर्फ ए.के. उर्फ यो को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला आकाश कश्यप पहले भी चार मामलों शामिल रह चुका है।

स्वच्छता अभियान को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए- सूद

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को राजधानी कॉलेज के सामने रिंग रोड पर फ्लाईओवर के नीचे स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान एक दिन, एक सप्ताह और एक महीने का नही, इसको हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर आशीष सूद ने स्वयं फ्लाईओवर के नीचे वर्षों से जमे हुए कूड़े के ढेर, मलवा, पत्थर आदि को नगर निगम के कर्मचारियों और जनकपुरी विधानसभा के कई कार्यकताओं के सहयोग से साफ किया। सूद ने कहा कि सेवा पखवाड़े में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि दिवाली से पहले दिल्ली में रिंग रोड और उसके आस-पास के क्षेत्रों को साफ और सुंदर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां श्रमदान कर रहे हैं ताकि इन हिस्सों को पूरी तरह चमकाया जा सके और इन्हें घर के आंगन की तरह साफ-सुथरा बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा की सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 75 से अधिक सेवाओं की शुरूआत की है। अस्पतालों का आधुनिकीकरण, डायलिसिस मशीनें की संख्या में वृद्धि, फायर स्टेशनों पर क्विक रिएक्शन व्हीकल्स की तैनाती, बस डिपो का नवीनीकरण आदि। इन नए कामों का उद्देश्य दिल्ली की जनता के जीवन को और आसान व सुविधाजनक बनाना है।

आज का यह सफाई अभियान उसी संकल्प का हिस्सा है कि सेवा केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा की स्वच्छता को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा तभी स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का महत्व है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छ दिल्ली अभियान में शामिल होना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारा छोटा सा योगदान है। उन्होंने सभी से 'सेवा' को उत्सव बनाने और स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील की।

सूद ने वहां उपस्थित पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से गश्त आदि के माध्यम से इस फ्लाईओवर के नीचे अवैध कब्जे और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में प्राथमिकता दिखाई।

पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर दो पड़ोसियों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को सशर्त रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मोगा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पड़ोसियों को एक आश्रम के निवासियों को पिज्जा और छाछ वितरित करने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से प्राथमिकी रद्द करने पर सहमति जताई थी।

कुट्टू के आटे के पकवान खाने से 200 लोगों की तबीयत बिगड़ी, इलाके में हड़कंप

नई दिल्ली

बाहरी दिल्ली में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से 200 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं, सूचना मिलने पर अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। बताया गया कि शुरूआती उपचार के बाद सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अफसरों ने राहत की सांस ली। जहांगीरपुरी अस्पताल में सोमवार देर रात से आज सुबह छह बजे तक इमरजेंसी वार्ड में मरीज पहुंचे थे।बीजेआरएम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विशेष यादव ने बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर,भलस्वा डेरी, लाल बाग और स्वरूप नगर इलाकों से मरीज आए थे। उन्होंने बताया कि सभी मरीज उल्टी की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आए थे। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है। किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उधर, स्थानीय दुकानदारों, विक्रेताओं और लोगों को बीट स्टाफ की ओर से जागरूक किया जा रहा है।

अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज-1 की रामलीला में हुआ प्रभु श्रीराम का जन्म

नई दिल्ली

अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज-1 के मंच व्यवस्था प्रमुख चंद्र बलवानी ने बताया कि मंगलवार की लीला में रामजन्म, ताड़का-सुबाहु वध और दशरथ-परशुराम संवाद को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। रामजन्म के समय अयोध्या में जो उत्सव का नजारा प्रस्तुत किया गया वह काबिले तारीफ था। रामलीला कमेटी के प्रेरक अनिल गुप्ता व कोषाध्यक्ष प्रमोद कोहली ने बताया कि रामजन्म के समय स्वर्गलोक से अप्सराओं द्वारा की जा रही पुष्प वर्षा को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे और ताड़का-सबाहु वध के दृश्य के बाद दशरथ-श्रवण कुमार संवाद का चित्रण काफी भावुक क्षण था। जिसे देखकर दर्शक अपने आसुंओं को नहीं रोक पा रहे थे। इस मौके पर अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज-1 के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र नागपाल ने कहा कि सभी को प्रभु श्रीराम के बताये हुए मार्ग पर चलना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम में आये हुए गणमान्य लोगों का कमेटी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया।

एक दिवसीय संपूर्ण बाल रामलीला का हुआ भव्य मंचन

नई दिल्ली

आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेस-2 के मंच पर एक दिवसीय सम्पूर्ण बाल रामलीला का मंचन हुआ। श्री गणेश पूजन, शंकर पार्वती संवाद, नारद मोह, रावण तपस्या एवं वैदवती संवाद, राम जन्म, तड़का वध, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, दशरथ केकई संवाद, राम बनवास, राम केवट मिलन, सीता हरण, लंका दहन, रावण वध की लीला का मंचन निपुण बाल कलाकारों के द्वारा किया गया। बाल कलाकारों का अभिनय देख दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। स्पेशल इफेक्ट, एलईडी ,कंप्यूटर, लाइट यंत्र ,लेजर लाइट का उपयोग से युद्ध कौशल आकर्षण का केंद्र बना। भूतों और राक्षसों का उन्माद डरावना व अद्भुत कौशल से परिपूर्ण था। युद्ध कौशल देख उपस्थित दर्शक रोमांचित हो गए। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह अनिल गुप्ता व सतीश गर्ग कोषाध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश ने किया। इस अवसर पर अनिल गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीराम के चरित्र का वर्णन शब्दों में तो हो ही नहीं सकता प्रभु श्रीराम अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया तथा युद्ध में भी उन्होंने सदा मयार्दाओं का ही पालन किया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। रामलीला के अध्यक्ष अशोक गर्ग व महामंत्री अनिल यादव ने सभी को महापर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रामलीला के डॉ रामकुमार, चन्दन शर्मा,उर्विका , ख्याति, घनश्याम अग्रवाल, राकेश गुप्ता, राजेंद्र खंडेलवाल, कमल हर मिलापी, देवेंद्र गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं, हमारी जीवनशैली का हिस्सा होनी चाहिए: महापौर

नई दिल्ली

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मंगलवार को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और स्वच्छता सैनिकों ने मिलकर परिसर को स्वच्छ करने का कार्य किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्लीवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ एवं हरित दिल्ली के संकल्प को मजबूत करना है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली का हिस्सा होनी चाहिए। यह कार्यक्रम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दिल्लीवासियों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। महापौर ने कहा कि इस अभियान ने न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई, बल्कि सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया।

संपादकीय

संयुक्त परिवार - त्रेतायुग सतयुग का पर्याय

कुदरत द्वारा रचित अनमोल खूबसूरत सृष्टि में भारत आदि अनादि काल से संस्कृति सभ्यता बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान संयुक्त परिवार प्रथा सहित सभी गुणों में विशाल वटवृक्ष की भांति फलता फूलता रहा है हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्वर्णलोक, स्वर्ग अनुभूति इस सृष्टि में धरती पर अपनों के बीच किया देखा और सुख भोगा है। उन अपार सुख के फूलों में से एक फूल है घर, परिवार, संयुक्त परिवार एक मजबूत सुख की छावं देने वाला, छत्रछाया देने वाला संयुक्त परिवार घर परिवार जहां बड़े बुजुर्गों के छत्रछाया में जीवन जीने, उनके फैसलों पर अमल करनें, आगे बढ़ाने और समर्पित भाव से जीवन जीने का सुख, अनमोल क्षण के साए में जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है। परंतु वर्तमान परिपेक्ष में धीरे-धीरे हमारे युवादेश के अधिकांश युवा पाश्चात्य संस्कृति के साए में बड़े बुजुर्गोंको नजरअंदाज कर, एकला चलो रे!! वाली नीति पर चलने की राह पर हैं किसी का लिखा एक खूबसूरत वाक्यांश बता दें, घर तब तक नहीं टूटता तब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है, अगर घर का हर सदस्य बड़ा बनने लगे तो घर टूटने में देरी नहीं लगती इसलिए अब समय आ गया है कि हमें बड़े बुजुर्गों की आज्ञा, उनकी छत्रछाया में जीने का अंदाज सीखने की तात्कालिक आवश्यकता है इसलिए हम इस आर्टिकल के माध्यम से आओ घरों को टूटने से बचाएं पर चर्चा करेंगे।

साथियों बात अगर हम महत्वपूर्ण फैसलों के बड़ों के हाथों से छुटने की करें तो, उम्र के फर्क. के साथ-साथ बड़े बुजुर्गों और बच्चों के मूल्यों में अंतर आ जाता है. मिसाल के लिए अगर बड़े बुजुर्ग बहुत धार्मिक हैं और उन्होंने बच्चों को भी वहीं संस्कार दिए तो भी जरूरी नहीं कि बच्चे उन्हीं संस्कारों को मानें, बस!!यहीं से टकराव की शुरूआत होती है। अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, ये भी देखा गया है कि आमतौर से अलग होने वाले माता-पिता और बच्चों के बीच अलग होने की वजह को लेकर कोई संवाद नहीं होता, इसलिए पताही नहीं चलता कि आखिर वजह क्या है।इसके अलावा भाई-बहनों के अलग मिजाज और माता-पिता का किसी एक बच्चे के प्रति गहरा लगाव भी अलगाव की वजह बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि परिवार में अलगाव तेजी से और रातों रात हो रहा है. बल्कि ये बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। कई बार छोटी सी घटना भी परिवार को तोड़ देती है। कहने को तो वो एक घटना होती है लेकिन उसके नतीजे दूरगामी होते हैं।

साथियों बात अगर हम घर में हर कोई बड़ा बनने के दो मुख्य कारणों की करें तो, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भूमंडलीकरण की वजह से उन देशों में भी परिवार टूट रहे हैं, जहां अकेले रहने की रिवायत नहीं है, भारत की ही बात करें तो बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों में या विदेशों में पलायन कर रहे हैं। वहीं जिन देशों में सरकार की ओर से बेहतर सुविधाएं नहीं मिलतीं वहां बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों के बीच मजबूत रिश्ता और एक दूसरे से लगाव देखने को मिलता है, इसकी मिसाल हमें यूरोप के कुछ देशों में देखने को मिलती है। बाहर बड़े शहरों या विदेश में रोजगार में जाने की वजह से माता-पिता से दूरी बन जाती है, साथ ही ऐसे परिवारों में आर्थिक रूप से लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते,स्वाभाविक रूप से वे अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, लिहाजा उन्हें अलग होने में कोई हिचक भी महसूस नहीं होती। ये भी देखा गया है कि जो किसी समुदाय के लोग एक दूसरे से ज्यादा करीब रहते हैं, उनके यहां बड़े परिवार भी एक छत के नीचे रहना पसंद करते हैं, ये भी हो सकता है कि असुरक्षा का भाव उन्हें ऐसा करने को कहता हो। शहरों में बड़े परिवार को साथ रखना आसान नहीं है,हर कोई बड़ा बनने एवं फैसला लेने की चाह रखता है इसलिए भी बुजुर्गों के साथ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है और गुजरते दौर के साथ ये स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन किसी भी समाज में जो सांस्कृतिक मूल्य बहुत मजबूत होते हैं, वो आसानी से खत्म नहीं होते. लिहाजा जिन समाज में परिवार के साथ रहने का चलन है वो आगे भी रहेगा, परंतु मुमकिन है कि आने वाले 20 साल में स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी।

टिटहरी: प्रकृति की मौन चेतावनी

डॉ सत्यवान सौरभ

भारत का ग्रामीण जीवन सदियों से प्रकृति के साथ गहरे संवाद में रहा है। खेत, मौसम और जीव-जंतु मिलकर किसान की दिनचर्या और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। इन सबके बीच टिटहरी एक ऐसा छोटा-सा पक्षी है, जो सामान्य आँखों से मामूली दिखता है, लेकिन किसानों और लोकजीवन की स्मृतियों में यह मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाला प्रहरी माना जाता है। यह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि धरती और आकाश के बीच संवाद का माध्यम है, एक मौन दूत है जो संकट और समृद्धि दोनों की आहट पहले ही दे देता है।

ग्रामीण अनुभव बताते हैं कि टिटहरी का व्यवहार मौसम और कृषि की दिशा तय करने में अहम संकेत देता है। यदि वह चार अंडे देती है तो चार महीने अच्छी वर्षा होने का विश्वास किया जाता है। जब वह ऊँचाई पर अंडे देती है, तो लोग मानते हैं कि सामान्य से अधिक वर्षा होगी। यदि कभी वह मजबूरी में छत या पेड़ पर अंडे दे, तो यह भीषण बाढ़ का संकेत माना जाता है। वहीं, यदि वह अंडे न दे तो यह सबसे डरावनी स्थिति होती है, क्योंकि लोग इसे अकाल का दूत मानते हैं। किसान कहते हैं कि जिस खेत में टिटहरी अंडे देती है, वह खेत खाली नहीं रहता। वहाँ फसल जरूर होती है। इस तरह यह पक्षी न केवल वर्षा और मौसम से जुड़े संकेत देता है बल्कि उपजाऊपन और अकाल जैसी चरम स्थितियों की चेतावनी भी बन जाता है।

लोकजीवन में एक और मान्यता है कि टिटहरी का मृत शरीर कुरुक्षेत्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता। चाहे यह तथ्य हो या प्रतीकात्मक कल्पना, लेकिन यह विश्वास उसे जीवन और अस्तित्व की रक्षा का प्रतीक बना देता है। टिटहरी को देखने वाला किसान समझ जाता है कि यह पक्षी उसकी मिट्टी, फसल और भविष्य का पहरेदार है। यही कारण है कि ग्रामीण लोकगीतों और कहावतों में भी टिटहरी का उल्लेख मिलता है। यह उन जीवों में से है जिनकी गतिविधियों पर पीढ़ियाँ भरोसा करती रही हैं।

अब सवाल उठता है कि जब विज्ञान मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह, राडार और कंप्यूटर मॉडल जैसे अत्याधुनिक साधन लेकर आया है, तब टिटहरी जैसे पक्षियों की भूमिका क्या रह जाती है। वास्तव में इसका उत्तर यही है कि विज्ञान और लोकअनुभव एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो टिटहरी जैसे पक्षी पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। हवा की नमी, तापमान का उतार-चढ़ाव, भूमि की नमी, जल स्तर का बढ़ना या घटना झ्र इन सबका असर उनके व्यवहार पर पड़ता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भाषा में इन्हें ह्लइकोसिस्टम इंडिकेटरह्व कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जो अपने आचरण के माध्यम से हमें पर्यावरणीय बदलावों की समय रहते जानकारी दे देते हैं। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान के औजारों का सहारा लिए बिना ही इन संकेतों को अनुभव के आधार पर समझा और उनका लाभ उठाया।

सदियों से किसान टिटहरी की गतिविधियों पर नजर रखते आए हैं। अगर वह अंडे देने का समय टाल दे तो किसान पहले से ही सतर्क हो जाते थे। यदि वह जमीन छोड़कर ऊँचाई पर चली जाए, तो वे अधिक वर्षा और संभावित जलभराव को लेकर चौकन्ने हो जाते थे। इस प्रकार लोकानुभव ने जो बातें कही हैं, वे वास्तव में वैज्ञानिक कारणों से जुड़ी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसानों ने इन्हें अपनी भाषा और प्रतीकों में व्यक्त किया।

वंशवाद की बेड़ियों में कैद लोकतंत्र !

सोनम लववंशी

यह सच है कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वंशवाद की परंपरा इसकी आत्मा को खोखला करती जा रही है। यह परंपरा किसी एक राजनीतिक दल या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में फैली हुई है। एक ओर लोकतंत्र अवसर की समानता और प्रतिनिधित्व की विविधता का वादा करता है, तो दूसरी ओर वंशवाद की यह बेल आमजन को हाशिये पर धकेलते हुए सत्ता को चुनिंदा घरानों के इर्द-गिर्द केंद्रित कर देती है। एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की हालिया रिपोर्ट इस सच्चाई को और स्पष्ट करती है। देश के कुल 5,204 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया कि इनमें से 1,107 यानी करीब 21 प्रतिशत प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि वंशवादी है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि लोकसभा में इनकी हिस्सेदारी 31 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर तीसरा सांसद किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आता है।

अगर दलों की बात करें तो कांग्रेस इस दौड़ में सबसे आगे दिखाई देती है। कांग्रेस के कुल प्रतिनिधियों में से 32 प्रतिशत नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस में अब भी राजनीति में प्रवेश का सबसे आसान टिकट वंश परंपरा ही है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी, जो अक्सर वंशवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, उसके भी 18 प्रतिशत प्रतिनिधि वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। वामपंथी दलों में यह आंकड़ा 8 प्रतिशत है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वहां वंशवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है, बल्कि यह केवल एक अलग तरह के संगठनात्मक ढांचे के कारण सीमित है। यदि सदनों की बात करें तो राज्य विधानसभाओं में 20 प्रतिशत, राज्यसभा में 22 प्रतिशत और विधानपरिषदों में 22 प्रतिशत प्रतिनिधि राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाती है कि चाहे संसद हो या राज्य का विधानमंडल, वंशवाद हर जगह अपनी गहरी पकड़ बनाए हुए है। कुछ राज्यों में यह प्रवृत्ति और भी गहरी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में वंशवादी प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश से 141 ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि वंशवादी है, जबकि महाराष्ट्र से 129, बिहार से 96 और कर्नाटक से 94 प्रतिनिधि इसी श्रेणी में आते हैं।

लोकतंत्र की आत्मा समान अवसर और समान अधिकार पर आधारित है। संविधान ने यह आश्वासन दिया है कि हर नागरिक को राजनीति में भाग लेने और सत्ता तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब राजनीति पर वंशवाद का कब्जा बढ़ता है तो यह अवसर केवल चुनिंदा परिवारों तक सीमित हो जाता है। आम युवाओं या नए चेहरों के लिए राजनीति में प्रवेश की राह और भी कठिन हो जाती है। दलों में टिकट वितरण का आधार अक्सर योग्यता या जनाधार न होकर पारिवारिक पहचान बन जाता है। इससे राजनीति में नई सोच और नई ऊर्जा का प्रवेश बाधित होता है। यह प्रवृत्ति केवल अवसर की असमानता ही पैदा नहीं करती, लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। जब जनता देखती है कि चुनावी मैदान में अधिकतर उम्मीदवार उन्हीं परिवारों से आते हैं जो दशकों से सत्ता पर काबिज हैं, तो उसके भीतर यह भावना पनपती है कि राजनीति एक बंद दरवाजा है, जहां आम आदमी की पहुंच नामुमकिन है। इस तरह लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार स्तंभ जनप्रतिनिधित्व धीरे-धीरे खोखला हो जाता है।वंशवाद का असर केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहता, यह नीति-निर्माण और शासन की दिशा को भी प्रभावित करता है। जब नेतृत्व विरासत में मिलने लगता है तो उसके भीतर जवाबदेही और संघर्षशीलता का भाव कमजोर हो जाता है। ऐसे नेता जिनका उदय केवल परिवार की पहचान के कारण हुआ हो, उनके लिए जनता की समस्याओं को गहराई से समझना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना प्रायः कठिन हो जाता है। वे सत्ता को अपने अधिकार की तरह देखना शुरू कर देते हैं, न कि जनता की सेवा का माध्यम। यही कारण है कि वंशवाद लोकतंत्र की उस मूल भावना के विपरीत खड़ा है जिसमें सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता मानी गई है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो वंशवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता। यह समाज में असमानताओं को और गहरा करता है। जब सत्ता कुछ परिवारों तक सीमित होती है, तो इससे सामाजिक अन्याय की जड़ें और मजबूत होती हैं। अवसर की समानता का सपना टूटता है और समाज में यह संदेश जाता है कि चाहे शिक्षा, क्षमता और प्रतिभा कितनी भी हो, अगर परिवारिक पहचान नहीं है तो राजनीति में स्थान पाना मुश्किल है। यह व्यवस्था उस समावेशी समाज की राह में बाधा बनती है जिसकी कल्पना संविधान ने की थी। यह भी विचारणीय है कि वंशवाद केवल वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता है। जब अगली पीढ़ी के सामने राजनीति का रास्ता पहले से तय हो, तो वे सत्ता को संघर्ष की बजाय विरासत मानने लगते हैं। यह लोकतंत्र को स्थायी नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति है। इसके विपरीत, अगर राजनीति योग्यता और जनसमर्थन पर आधारित हो, तो उसमें संघर्षशील, जनता से जुड़े और जवाबदेह नेता उभरते हैं।

इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल अपने टिकट वितरण में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दें। जनता को भी इस प्रवृत्ति को पहचानकर ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देनी होगी जिनकी राजनीति उनकी अपनी मेहनत और जनता से जुड़ाव के कारण बनी हो। चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को भी इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हों। भारत का लोकतंत्र अपनी विविधता और समावेशी प्रकृति के कारण दुनिया में अलग पहचान रखता है। लेकिन अगर वंशवाद की बेल इसी तरह फैलती रही तो यह लोकतंत्र को भीतर से कमजोर कर देगी। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ तभी साकार होगा जब राजनीति हर नागरिक के लिए खुला मंच बने, न कि कुछ परिवारों की निजी जागीर। वंशवाद के खिलाफ यह संघर्ष केवल राजनीतिक सुधार का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का संघर्ष है। आखिरकार, लोकतंत्र की ताकत उसकी जनता होती है। अगर जनता ही अवसर की समता और समान प्रतिनिधित्व से वंचित कर दी जाए तो यह लोकतंत्र के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न है।

सलिए वंशवाद को समाप्त करना केवल

क्या स्वरचित चक्रव्यूह में उलझ चुका इस्लामी जगत

तनवीर जाफरी

कतर की राजधानी दोहा में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर गत 9 सितंबर को किए गए इजराइली हवाई हमले के बाद पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। सबसे अधिक आश्चर्य दुनिया को इस बात को लेकर है कि कतर मध्य एशिया में अमेरिका का सबसे खास सहयोगी देश है। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घनिष्टता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी गत मई में ही कतर के अमीर ने लगभग 400 मिलियन डालर अर्थात लगभग 3,300 करोड़ रुपये का एक ऐसा बोइंग 747-8 लग्जरी हवाई जहाज राष्ट्रपति ट्रंप को भेंट किया जो अमेरिका के वर्तमान एयर फोर्स वन विमान के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कतर अमेरिका का इतना खास है कि आज विश्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा अल उदीद एयर बेस है जोकि कतर की राजधानी दोहा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ 11,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक हर समय तैनात रहते हैं। यहीं अमेरिका का केंद्रीय कमांड भी है जिसके द्वारा वह इस पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान संचालित करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई सैन्य अड्डे इराक, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात व कुवैत में भी हैं। इस तरह 18 मुस्लिम बहुल देशों में छोटे बड़े व अलग अलग सैन्य संचालन सुविधाओं से युक्त कई अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इन देशों में अमेरिकी सैन्य बेस का अर्थ है कि उन देशों को अमेरिका ने सैन्य सुरक्षा प्रदान की हुई है। और प्रायः ऐसे अधिकांश देश अपनी आंतरिक सुरक्षा का ढांचा तो जरूर रखते हैं परन्तु उनके पास पेशेवर सेना या सैन्य साजो सामान नहीं होते। इसी लिए 9 सितंबर को कतर पर हुये हमले के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा अल उदीद एयर बेस दोहा में होने के बावजूद दोहा में ही इस्राईली सेना ने हवाई हमले का सहस कैसे किया ? क्या इस्राईल ने अमेरिका की कोई परवाह नहीं की ? या अमेरिका को इस हमले की पूर्व सूचना दे दी गयी थी ? अगर अमेरिका को इन हमलों का पता था तो उसने कतर को समय पूर्व सूचित क्यों नहीं किया ? और इन सबसे बड़ा सवाल यह कि यदि अमेरिकी एयर बेस होने के बावजूद अमेरिका कतर की इसी तरह की सुरक्षा करेगा तो ऐसे सैन्य अड्डों का लाभ क्या ? और इसी से निकलता इस वक़्त का सबसे अहम सवाल

कि तो क्या कतर सहित अमेरिकी सुरक्षा पर आश्रित सभी देशों को अपना ह्यसुरक्षा गार्ड ह्य बदलने की जरुरत है ? या फिर इस्लामी जगत की एकजुटता और संयुक्त सैन्य आत्मनिर्भरता ही अकेला रास्ता है जो मुस्लिम जगत को अमेरिकी झ्र इस्राईली शिकंजे से मुक्त करा सकता है ?

दरअसल 9 सितंबर को दोहा पर इस्राइली हमले के बाद गत 15 सितंबर को दोहा में अरब-इस्लामी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी शिखर सम्मेलन में मिस्त्र ने यह प्रस्ताव पेश किया कि नाटो की संयुक्त सेना की ही तर्ज पर इस्लामी देशों की एक ऐसी संयुक्त सेना यानी अरब यूनिफाइड आर्मी का गठन किया जाये जिसमें सेना, वायुसेना और कमांडो इकाइयों का तालमेल, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स को एकीकृत किया जा सके। मिस्त्र के इस प्रस्ताव को ईरान, इराक, सऊदी अरब, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों से समर्थन हासिल हुआ है। इस प्रस्तावित संयुक्त सेना का उद्देश्य यह है कि अगर किसी मुस्लिम देश पर हमला हो, तो सभी सदस्य मुस्लिम देश मिलकर जवाब दें। यह बल नौसेना, वायुसेना और जमीनी इकाइयों पर आधारित होगा, जिसमें कमांडो, आतंकवाद-रोधी और शांति रक्षा इकाइयां शामिल होंगी। इस तरह का प्रस्ताव कोई पहली बार नहीं आया है। बल्कि इससे पहले 2015 में भी मिस्त्र ही ऐसा प्रस्ताव ला चुका है परन्तु उसपर न कोई अमल हुआ न ही पुनर्विचार।

परन्तु अब इस्राईल द्वारा गजा में किया जा रहा जनसंहार, उसपर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की खामोशी और इसी खतरनाक खामोशी की आड़ में इस्राईल द्वारा मध्य एशिया में अपने पांव पसारते हुये अपने ग्रेटर इस्राईल नापाक मंसूबों पर तेजी से आगे बढ़ने की योजना ने इस्लामी जगत को यह सोचने के लिये बाध्य कर दिया है कि यदि उन्होंने अपने को यथाशीघ्र एकजुट नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में एक एक कर सभी मुस्लिम राष्ट्रों को अमेरिका इस्राईली की ऐसी ही साजिश का शिकार होना पड़े ? दुनिया को इस चाल को भी समझने की जरुरत है कि पूरे विश्व में लोकतान्त्रिक व्यवस्था की वकालत करने वाले अमेरिका को इस्लामी जगत के शाहों,बादशाहों व प्रिंस के शासन से कोई आपत्ति नहीं होती। इस पूरे कुचक्र का कारण यह है कि यह पूरा मध्य एशिया क्षेत्र तेल सम्पन्न इलाका है और अमेरिकी इन तेल संसाधनों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण रखना चाहता है। अपने इसी उद्देश्य के तहत वह इस क्षेत्र में शिया वर्चस्व का भय दिखाकर ईरान के साथ अन्य अरब देशों को एकजुट भी नहीं होने देता। परन्तु ईरान ने 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद तथा पहलवी शासन का अमेरिकी समर्थित राजतन्त्र उखाड़ फेंकने के बाद न केवल अपने तेल भंडारों को अमेरिकी गिद्ध दृष्टि से सुरक्षित किया बल्कि स्वयं को शिक्षा,विज्ञान,शोध व सैन्य यहाँ तक कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इतना मजबूत किया कि पिछले दिनों दुनिया भर में अपनी आक्रामकता दिखने वाले इस्राईल को ईरान के सामने घुटने टेकने पड़े। यहाँ तक कि अपने ऊपर हुये अमेरिकी हवाई हमले का बदला लेकर भी ईरान ने यह साबित कर दिया कि ईरान अन्य अमेरिकी पिछलग्गू अर्ब देशों से बिल्कुल भिन्न सोच व नीति रखने वाला लोकतान्त्रिक देश है। ईरान ने उन कठिन परिस्थितियों में स्वयं को इतना मजबूत किया जबकि अमेरिका ने दशकों से ईरान पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी चाटुकारिता या खुशामद परस्ती नहीं बल्कि नेक नीयती ,मानवता, शिक्षा, संस्कार, वैज्ञानिक शोध तथा इनसे आने वाली एकजुटता व आत्मनिर्भरता ही किसी भी देश को व उसके स्वाभिमान को बचा सकती है। अन्यथा कतर की ही तरह अन्य आने वाले दिनों में अमेरिकी पिछलग्गुओं को भी ऐसे ही संकटों का सामना करना पड़ेगा। परस्पर विश्वास की कमी के साथ साथ वैसे भी दशकों से अमेरिकी पर आश्रित बना बैठा अधिकांश इस्लामी जगत स्वरचित चक्रव्यूह में ही इतना उलझ चुका है कि उससे निकल पाना आसान नजर नहीं आता।

2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए मिशन मोड पर भाजपा

अशोक भाटिया

तमिलनाडु में अगले साल की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा तमिलनाडु में भी एनडीए गठबंधन का विस्तार कर रही है और नए दलों को शामिल करके चुनाव में सत्तधारी पार्टी डीएमके के गठबंधन को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने मिशन मोड रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनाव में डीएमके विरोधी वोट विभाजित न हों। भाजपा यहां हर जाति वर्ग के लोगों को साधने के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रही है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि वोटों के विभाजन को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को फायदा हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इखढ एनडीए के दायरे में छोटे दलों को शामिल करने पर काम कर रही है।

4 अप्रैल को तमिल नववर्ष से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ राज्य में गठबंधन बनाने की घोषणा की। हालाँकि एआईएडीएमके ने एक समय तमिलनाडु के द्रविड़-प्रभुत्व वाले राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन

अब इसका वही प्रभाव नहीं है जो पूर्व मुख्यमंत्री जे। जयललिता के समय था।पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के। पलानीस्वामी (ईपीएस) की अगुआई वाली पार्टी अपने पार्टी सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ। पनीरसेल्वम (ओपीएस) के साथ नियंत्रण के लिए तीखे संघर्ष के बाद सत्ता में बनी हुई है। 2016 से 2021 तक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से जुड़े रहने के कारण, ईपीएस ने भाजपा नेतृत्व के साथ कामकाजी संबंध का आनंद लिया। पिछले हफ़्ते चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई घोषणा में भी स्पष्ट राजनीतिक संदेश था कि ईपीएस मौजूदा एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके गठबंधन सरकार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं।

अब तमिलनाडु में भाजपा की कोशिश एनडीए का और कुनबा बढ़ाने की है. तमिल पॉलिटिक्स के समीकरणों का ध्यान रख भाजपा एनडीए में कुछ और नई पार्टियों को शामिल कराने की तैयारी में है. भाजपा की नजर एक-एक वोट पर है. तमिलनाडु की चुनावी फाइट में भाजपा एंटी इनकम्बेंसी और एंटी डीएमके, दोनों ही वोट बिखरें ना, इस रणनीति पर मिशन मोड में काम कर रही है.

पार्टी ने इसके लिए अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. तमिलनाडु में एनडीए की अगुवाई कर रहे एआईएडीएमके के नेता ई पलानीस्वामी (ईपीएस) इसी हफ्ते दिल्ली आए थे, जहां उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैराथन मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात में एआईएडीएमके में पुराने नेताओं की वापसी पर भी बात हुई थी.

एआईएडीएमके सूत्रों के मुताबिक ईपीएस ने अमित शाह से यह कहा कि भाजपा को उनकी पार्टी के निष्कासित नेताओं का ठिकाना नहीं बनना चाहिए. ऐसा करने से गठबंधन की एकता और दोनों दलों के आपसी संबंधों पर असर पड़ सकता है. एआईएडीएमके से न्ष्किासित नेताओं को लेकर दोनों ही नेताओं की बातचीत में कोई हल नहीं निकला.ईपीएस और अमित शाह, दोनों ही नेताओं में इस बात पर सहमति बनी कि अगले महीने से तमिलनाडु में संयुक्त अभियान चलाया जाएगा और डीएमके सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, उनको जनता के बीच ले जाया जाएगा. सूत्रों की मानें तो एआईएडीएमके से निष्कासित ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) को भाजपा अपने साथ लेना चाहती है और वह दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी में कमल निशान वाली पार्टी का दामन थाम सकते हैं.

ओपीएस के भाजपा में शामिल होने की बात एआईएडीएमके को पसंद नहीं आ रही. एआईएडीएमके नेता ईपीएस यह भी चाहते हैं कि तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके को एनडीए में साथ लिया जाए. ईपीएस का मानना है कि पिल्लै जाति से आने वाले विजय सूबे की अगड़ी जातियों को एनडीए के पाले में लाने में अहम साबित हो सकते हैं. हालांकि, विजय की एनडीए में एंट्री के लिए भाजपा तैयार नहीं है.

भाजपा का मानना है कि विजय की पार्टी डीएमके के वोट काट रही है. भाजपा और एआईएमडीएमके, दोनों दलों में टीटी दिनाकरन और पीएमके को लेकर भी मतभेद बने हुए हैं. पीएमके पहले एनडीए में शामिल रह चुकी है. सूत्रों के मुताबिक भाजपा चाहती है कि ईपीएस अगर टीटी दिनाकरन की एआईएडीएमके में वापसी नहीं चाहते, तो उनकी पार्टी को एनडीए में शामिल कराया जाए.

भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि थेवर जाति के दिनाकरन एनडीए को मजबूती दे सकते हैं. जहाँ तक उनकी चाची और जयललिता की करीबी शशिकला का प्रश्न है, यह संभव है कि वे एनडीए के पक्ष में कैंपेन करें और विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की जाए. गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 75 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी. 2024 के लोकसभा चुनावों में, ऊटङ सांसदों ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की। ऊटङ को 46.9 प्रतिशत वोट मिले। यह 1991 के बाद से ऊटङ द्वारा सबसे अधिक वोट शेयर था। 2024 में, भाजपा ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर जगह हार गई। भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनावों में 3.6 प्रतिशत, 2024 में 5.5 प्रतिशत वोट मिले। 2009 में, इसे 2.3 प्रतिशत वोट और 2004 में 5.1 प्रतिशत वोट मिले। द्रमुक के पास अन्नाद्रमुक और भाजपा की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है। स्टालिन के पास पलानीस्वामी की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है, लेकिन उन्हें सत्ता विरोधी लहर से भी पीड़ित होने की संभावना है। तमिलनाडु में, भाजपा ने अन्नाद्रमुक को महत्व दिया है। डेढ़ साल के अंतराल के बाद, भाजपा और अन्नाद्रमुक ने गठबंधन में फिर से प्रवेश किया है।

डीएमके की अगुवाई वाले कांग्रेस-लेफ्ट और अन्य छोटी पार्टियों के गठबंधन को 234 में से 159 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

अकेले डीएमके ने 133 सीटें जीती थीं, जो पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से 15 ज्यादा थीं. तमिलनाडु में हर पांच साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है. ऐसे में एनडीए को सत्ता की उम्मीद नजर आ रही है.

एआईएडीएमके का मानना है कि पिल्लई जाति से आने वाले विजय अगाड़ी जाति के वोट ला सकते हैं।

जापान में नया प्रधानमंत्री चुने जाने की कवायद शुरू

एजेंसी

टोक्यो। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफा देने के बाद उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए होने वाले आगामी चुनाव के लिए आज आधिकारिक अभियान की शुरूआत की। जापान के एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चार अक्टूबर को एलडीपी के 295 सांसदों और करीब दस लाख पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के नये नेता के चुनाव में मतदान करेंगे। पार्टी के शीर्ष पद के लिए पांच उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिसमें कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची, इशिबा की सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री ताकायुकी कोबायाशी शामिल हैं।पार्टी के इस आंतरिक चुनाव का नारा है- एलडीपी का परिवर्तन। इशिबा के विकल्प के रूप में एलडीपी एक ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो देश में राजनीतिक स्थिरता और पार्टी के प्रति मतदाताओं के समर्थन को बहाल कर सके। विशेषज्ञों का कहना है कि नये नेता के लिए विपक्षी दलों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान इस समय तनावपूर्ण सुरक्षा वातावरण का सामना कर रहा है।

गाजा सिटी में इजराइली हमलों के बीच दो अस्पताल बंद, मौतों का आंकड़ा 65 हजार पार

गाजा सिटी। इजराइली हमलों के चलते गाजा सिटी स्थित अल-रंतीसी बाल अस्पताल और नेत्र अस्पताल पूरी तरह से सेवाओं से बाहर हो गए हैं। अल-रंतीसी अस्पताल को हाल ही में सीधे निशाना बनाया गया था, जिससे उसकी इमारत और आवश्यक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशनिंग यूनिट, पानी के टैंक और सोलर पैनल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यह अस्पताल गाजा में कैंसर और गुर्दे की गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए एकमात्र विशेष चिकित्सा केंद्र माना जाता है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि सुरक्षा बल गाजा पट्टी में स्वास्थ्य सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बना रहे हैं। सुरक्षित मार्ग न होने के कारण मरीजों और घायलों के लिए अस्पताल पहुंचना बेहद कठिन हो गया है। मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इसी बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 07 अक्तूबर 2023 से अब तक गाजा पट्टी में इजराइली हमलों में 65,344 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,66,795 लोग घायल हुए हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही 61 लोगों की मौत और 220 से अधिक के घायल होने की पुष्टि हुई है। मंत्रालय का कहना है कि कई शव अब भी मलबे और सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन लगातार बमबारी के कारण एंबुलेंस और राहत दल वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

दुनिया भर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चीन आने पर स्वागतः चीनी विदेश मंत्रालय

बीजिंग। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के प्रवासी कुशल कामगारों के लिए वीजा नियम कड़े करने के बीच चीन ने कहा है कि वह दुनियाभर के उद्योगों और क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चीन आने पर स्वागत करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यह बात कही।इस बीच ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर एक लाख डालर किए जाने के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि चीन अमेरिकी वीज़ा नीतियों पर टिप्पणी नहीं करता है।अमेरिका के इस नीतिगत बदलाव से देश के तकनीकी उद्योग के पेशेवरों पर पड़ने वाले प्रभाव और हाल के वर्षों में विदेशी तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने की बाबत चीन की नीतियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि उनका देश दुनियाभर की उत्कृष्ट प्रतिभागों के चीन आगमन का स्वागत करेगा।वैश्वीकरण के युग में प्रतिभाओं के सीमा-पार प्रवाह के दुनिया भर में तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास को गति देने संबधी एक अन्य प्रश्न के संबंध में गुओ ने कहा, चीन दुनिया भर के सभी उद्योगों और क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चीन आने, चीन में जड़ें जमाने और व्यक्तिगत करियर विकास करने का स्वागत करता है। इससे मानव समाज की निरंतर प्रगति को संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जा सकेगा।

सुशीला कार्की कैबिनेट के चार मंत्रियों ने ली शपथ, अंतिम समय में एक नाम हटाया गया

काठमांडू। अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की कैबिनेट में शामिल होने के लिए चार नवनियुक्त मंत्रियों ने शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में एक विशेष समारोह में इन्हें शपथ दिलाई। पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक महावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल और कृषि विशेषज्ञ मदन परियार ने मंत्री पद की शपथ ली। सिन्हा ने उद्योग, कानून और भूमि व्यवस्था मंत्री, पुन ने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, खरेल ने संचार और सूचना मंत्री तथा परियार ने कृषि मंत्री के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव के पद से इस्तीफा देने वाली डॉ. संगीता मिश्रा को लेकर विवाद होने के बाद उनका नाम अंतिम समय में शपथग्रहण की सूची से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को राष्ट्रपति पौडेल से डॉ. मिश्रा को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपने की सिफारिश की थी।

दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला को उपहार देने के मामले में यूनिफिकेशन चर्च की प्रमुख हान हक-जा गिरफ्तार

एजेंसी

सियोल (दक्षिण कोरिया)। दक्षिण कोरिया के सर्वाधिक शक्तिशाली यूनिफिकेशन चर्च धार्मिक साम्राज्य की प्रमुख हान हक-जा को आज जेल भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें दक्षिणी सियोल स्थित सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया गया। उन्हें अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी किम कियोन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया। यूनिफिकेशन चर्च विशाल धार्मिक साम्राज्य है। इसकी स्थापना दिवंगत रेवरेंड मून सन-म्यांग ने की थी।द कोरिया टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी सियोल स्थित सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देश की पूर्व प्रथम महिला किम कियोन को चुनाव के समय उपहार देने के आरोप में हान हक-जा को हिरासत में लेने का आदेश दिया था।

कोर्ट में पेशी के दौरान अभियोजकों ने हान हक-जा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। कोर्ट ने अभियोजकों की मांग स्वीकार कर ली। इस गिरफ्तारी को देश के राजनीतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान को जकड़े हुए एक घोटाले में अब तक का सबसे नाटकीय मोड़ माना जा रहा है। अभियोजकों का आरोप है कि 82 वर्षीय हान हक-जा ने यून नामक एक पूर्व चर्च अधिकारी के साथ मिलकर 2022 में पीपल पावर पार्टी के सांसद क्वेओन सियोंग-डोंग को 10 करोड़ वॉन देने की साजिश रची थी। बदले में, क्वेओन से यह अपेक्षा की गई थी कि अगर यून सुक येओल राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वह चर्च के लिए लाभ सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। आरोप है कि हान ने कथित तौर पर चर्च के अधिकारियों को किम को महंगे हैंडबैग और आभूषण सहित विलासितापूर्ण उपहार देने का आदेश दिया था। इस बीच चर्च ने इन आरोपों का खंडन किया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने गिरफ्तारी को इस आधार पर उचित ठहराया कि हान के बाहर रहने से सबूत नष्ट होने का खतरा है। हान को व्हीलचेयर के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। यह मामला येओल के राष्ट्रपति पद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की दक्षिण कोरिया में चल रही विशेष जांच के तहत व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।

फ्रांस के कई शहरों में फिलिस्तीनी झंडा नहीं फहराने की सरकारी चेतावनी का उल्लंघन

एजेंसी

पेरिस। फ्रांस में 80 से अधिक नगरपालिकाओं ने फिलिस्तीनी ध्वज फहराया, जबकि सरकार ने इसे न करने की चेतावनी जारी की थी। यह कदम राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की तैयारी के बीच आया है। इस मान्यता की घोषणा ने इजराइल में राजनीतिक स्तर पर कड़ी आलोचना को जन्म दिया है। फ्रांस के बड़े शहरों - जैसे ल्योन, नांतेस, रेन और बेसांकॉन के नगरपालिकाओं ने फिलिस्तीनी झंडा फहराया। पेरिस में भी वामपंथी नगर परिषद के सदस्यों ने मेयर एन हिदाल्गो के विरोध के बावजूद आधे घंटे के लिए सिटी हॉल पर

झंडा लगाया। अंदरूनी मंत्रालय ने बताया कि देशभर की 34,875 नगरपालिकाओं में से केवल 86 नगरपालिकाओं ने फ़िलिस्तीनी ध्वज फहराया। मंत्रालय ने इस कदम को सरकारी आदेश की अवहेलना बताया है। फ्रांस में यह घटना देश में फिलिस्तीनी मुद्दे पर बढ़ती संवेदनशीलता और स्थानीय राजनीति में इसे लेकर अलग-अलग रुझानों को उजागर करती है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने संघीय व्यापार आयुक्त रेबेका स्लॉटर को बर्खास्त करने के ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा

एजेंसी

वाशिंगटन (अमेरिका)। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघीय व्यापार आयुक्त रेबेका स्लॉटर को बर्खास्त करने के फैसले को कम से कम अंतरिम आधार पर बरकरार रखा। न्यायाधीशों ने कहा कि वे कार्यकारी शक्ति के दायरे को लेकर चल रहे इस बड़े विवाद की समीक्षा में तेजी लाएंगे। एबीसी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, रूढ़िवादी बहुमत वाले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की व्याख्या नहीं की, लेकिन यह कदम हाल ही में दिए गए अन्य आदेशों के अनुरूप रहा। इन फैसलों में महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को व्यापक सम्मान दिया गया। स्लॉटर को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। ट्रंप ने स्लॉटर को बिना किसी कारण के विशुद्ध रूप से नीतिगत मतभेदों का हवाला देते हुए हटा दिया। न्यायाधीश एलेना कागन, सोनिया सोतोमयोर और केतनजी ब्राउन जैक्सन ने संघीय

कानून का हवाला देते हुए इस फैसले से असहमति जताई। कागन ने कहा कि राष्ट्रपति बिना किसी कारण के किसी संघीय व्यापार आयुक्त को बर्खास्त नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि दिसंबर में होने वाली सुनवाई के दौरान सीधे इस मिसाल पर विचार किया जाएगा और इस बात की जांच होगी कि क्या संघीय व्यापार आयुक्तों का निष्कासन सुरक्षा शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। एक अलग आदेश में, न्यायालय ने बर्खास्त मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड की सदस्य कैथी हैरिस और बर्खास्त नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड की सदस्य ग्वेने विलकॉक्स की त्वरित अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जयशंकर की न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेशमंत्री रुबियो और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात

एजेंसी

न्यूयॉर्क (अमेरिका)। भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर ने यहां अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। इसके अलावा उनकी यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ मुलाकात हुई। जयशंकर ने इस अवसर के फोटो और संक्षिप्त विवरण अपने एक्स हैंडल पर साझा किए हैं। जयशंकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, आज सुबह न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रुबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति हुई। हम संपर्क में बने रहेंगे। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात पर खुशी जताई। जयशंकर ने दूसरी पोस्ट में लिखा, आज न्यूयॉर्क में यूरोपीय संघ के विदेशमंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में उनसे मिलकर मुझे खुशी हुई। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास को मेजबानी के लिए धन्यवाद। यह बहुपक्षवाद, भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, यूक्रेन संघर्ष, गाजा, ऊर्जा और व्यापार पर

विचारों के खुले आदान-प्रदान का अवसर रहा। भारतीय विदेशमंत्री जयशंकर की इन नेताओं से यह बातचीत ऐसे समय पर हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का उच्चस्तरीय 80वां सत्र शुरू होने वाला है। रुबियो से उनकी मुलाकात लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में हुई। रुबियो और जयशंकर के बीच यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद आमने-सामने की पहली मुलाकात है। इसके साथ ही भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। जयशंकर 27 सितंबर को यूएनजीए मंच से वक्तव्य देंगे।

परमाणु हथियार संधि पर पुतिन का ट्रंप को एक वर्ष का विस्तार प्रस्ताव

एजेंसी

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम संधि 'न्यू स्टार्ट' को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। यह संधि 05 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है। 'न्यू स्टार्ट' संधि के तहत दोनों देशों के लिए 1,550 तैनात परमाणु वॉरहेड की सीमा तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संधि का नवीनीकरण या विकल्प नहीं हुआ तो दोनों देश इस सीमा को पार कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि यह कदम वैश्विक परमाणु अप्रसार के हित में है और इससे वाशिंगटन के साथ हथियार नियंत्रण पर संवाद को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव तभी व्यवहार्य होगा, जब अमेरिका भी समान रूप से इस संधि

की शर्तों का पालन करे और सामरिक संतुलन को कमजोर करने वाले कदम न उठाए। पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, रूस 05 फरवरी 2026 के बाद एक वर्ष तक न्यू स्टार्ट संधि की केंद्रीय सीमाओं का पालन करने को तैयार है। इसके बाद हालात की समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध के कारण गहरे मतभेद बने हुए हैं और इसी वजह से अब तक नई संधि या नवीनीकरण पर औपचारिक वार्ता शुरू नहीं हो सकी है। वहीं ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे भविष्य में चीन को भी शामिल कर नई परमाणु हथियार नियंत्रण संधि करना चाहते हैं, जिसे बीजिंग ने खारिज कर दिया है। हथियार नियंत्रण मामलों पर काम करने वाले आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बल ने पुतिन के इस कदम को ÷सकारात्मक और स्वागत योग्य÷ बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका भी इसका जवाब देगा और दोनों नेता दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़े सुरक्षा खतरे को कम करने की दिशा में कदम उठाएंगे।

मोल्दोवा में रूस समर्थित अशांति की साजिश का भंडाफोड़, 74 लोग गिरफ्तार

एजेंसी

किशिनाउ। मोल्दोवा की पुलिस ने देशभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 लोगों को हिरासत में लिया। अधिकारियों का कहना है कि ये गिरफ्तारियां एक कथित रूस समर्थित साजिश के तहत की गईं, जिसका उद्देश्य आगामी संसदीय चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे भड़काना और देश को अस्थिर करना था। मुख्य अभियोजक विक्टर फुर्टुना ने बताया कि पुलिस ने 250 छापेमारी अभियान चलाए, जिनमें 100 से अधिक संदिग्धों को निशाना बनाया गया। हिरासत में लिए गए लोगों को 72 घंटे तक पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा। मोल्दोवा 101

सीटों वाली संसद के लिए चुनाव कराने जा रहा है, जिसे देश की भावी दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। यह चुनाव तय करेगा कि मोल्दोवा यूरोपीय संघ की सदस्यता की ओर बढ़ेगा या फिर रूस के और करीब जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह पूरा षड्यंत्र ÷रूसी संघ से संचालित, आपराधिक तत्वों के ज़रिए तैयार किया गया था। अधिकारियों का मानना है कि रूस समर्थित ताकतें चुनावों से पहले मोल्दोवा में हिंसा और अशांति फैलाकर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करना चाहती थीं।

कांगो में इबोला फैलने से रोकने के लिए तत्काल मदद की अपील

एजेंसी

जिनेवा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला प्रकोप की स्थिति गंभीर होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट महासंघ (आईएफआरसी) ने सोमवार को कहा कि प्रकोप के केंद्र बुलापे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से दबाव में हैं और आवश्यक आपूर्तियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं।

महासंघ ने चेतावनी दी है कि साफ पानी और सुरक्षा उपकरणों की कमी के चलते स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। इस संकट से निपटने के लिए आईआरएफसी ने 2 करोड़ स्विस फ्रैंक (करीब 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तत्काल सहायता की अपील की है। रेड क्रॉस के किन्शासा प्रतिनिधिमंडल प्रमुख

एरियल केस्टेन्स ने बयान में कहा, स्वास्थ्य केंद्रों पर अत्यधिक बोझ है, ज़रूरी आपूर्ति उपलब्ध नहीं है और पूरा इलाका बिजली के बिना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, अब तक कांगो में 48 पुष्ट और संभावित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 31 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलापे का मुख्य आइसोलेशन सेंटर लगभग भर चुका है, जबकि एकमात्र ट्रीटमेंट सेंटर पहले ही 119% क्षमता पर काम कर रहा है। आईआरएफसी ने कहा कि यदि तुरंत संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो वायरस तेजी से ÷कमजोर समुदायों में फैल सकता है।÷ कांगो रेड क्रॉस के अध्यक्ष ग्रेगॉयर मेटेसो ने कहा, ÷स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का मतलब है समुदायों की सुरक्षा। डीआरसी को तत्काल सहयोग चाहिए, खासकर दूर-दराज और संसाधन-विहीन क्षेत्रों में। डब्ल्यूएचओ ने कासाई प्रांत में स्वास्थ्यकर्मियों और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है।

नाटो हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हंगामा

एजेंसी

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सोमवार को रूस के लड़ाकू विमानों द्वारा एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ का मुद्दा गूंज उठा। ब्रिटेन और पोलैंड के विदेश मंत्रियों ने रूस को कड़ी चेतावनी दी कि यदि ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो नाटो बल हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए सीधे जवाब देंगे। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने रूस पर आरोप लगाया कि वह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को तीन हथियारबंद रूसी लड़ाकू विमानों का उनकी सीमाओं में प्रवेश उनकी संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है।

डेनमार्क के विदेश मंत्री ने भी चिंता जताई कि यूक्रेन के बाद रूस के अन्य पड़ोसी देशों को खतरा महसूस हो रहा है। वहीं अमेरिका के नए राजदूत और पूर्व राष्ट्रीय

सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने साफ कहा, अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो के हर इंच क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर, रूसी प्रतिनिधि ने घटना को कमतर बताते हुए यूरोपीय देशों पर हमला बोला और उन्हें संकुचित सोच वाले रूस विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप का रूस के प्रति घृणा और भय अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुका है। इस बीच, चीन ने रूस की आलोचना से परहेज किया और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा गलतफहमियों और गलत आकलनों से बचने की अपील की।

इक्वाडोर की जेल में दंगा, 14 कैदियों की मौत, 14 घायल

एजेंसी

क्विटो। दक्षिणी इक्वाडोर में हुई जेल हिंसा में कम से कम 14 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस प्रमुख विलियम कैले ने बताया कि बंदरगाह शहर मचाला की जेल में आपसी गिरोह संघर्ष के चलते यह झड़प हुई। काले के अनुसार कैदियों ने जेलकर्मियों पर हमला कर दिया जिसमें एक गार्ड की मौत हो गई और कई अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। उन्होंने बताया, जेल के अंदर से कैदी गोलीबारी कर रहे थे, बम और ग्रेनेड फेंक रहे थे। अराजकता के दौरान कुछ कैदी जेल से भाग निकले, लेकिन अब तक 13 को दोबारा पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार करीब 40 मिनट की कड़ी कार्रवाई के बाद जेल पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि इक्वाडोर पिछले कुछ वर्षों से लगातार जेल दंगों से जूझ रहा है। इन घटनाओं में अब तक सैकड़ों कैदी मारे जा चुके हैं। राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ की सरकार का कहना है कि गिरोहों के बीच इलाकों और ड्रग्स तस्करी पर नियंत्रण की लड़ाई ही इन हिंसक घटनाओं की जड़ है।

हमास ने फलस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट उतारा, भीड़ करती रही नारेबाजी; इस्राइल की मदद का था आरोप

एजेंसी

गाजा। फलस्तीन के गाजा और वेस्ट बैंक में इस्राइल की तरफ से जारी हमलों के बीच कट्टरपंथी संगठन हमास से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि हमास ने रविवार को तीन फलस्तीनी नागरिकों को सरेआम सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। जिन लोगों की जान ली गई है, उन पर इस्राइल की मदद करने का आरोप था। हमास से संबंधित टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में तीन लोगों को सड़क पर घुटने के बल बैठे देखा जा सकता है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जबकि उनके पीछे तीन बंदूकधारी ऑटोमैटिक बंदूकें लेकर खड़े हैं। इस दौरान बंदूक लिए एक व्यक्ति अरबी में तीनों की मौत का आदेश पढ़ता है। मध्य पूर्व रिपोर्टिंग और विश्लेषण से जुड़ी समिति ने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ को जो जानकारी उपलब्ध कराई, उसके मुताबिक हमास के लड़ाकों ने कहा, ÷फलस्तीनी क्रांतिकारी कानून की सामग्री के अनुसार और फलस्तीनी क्रांतिकारी अदालत के आधार पर, उन लोगों के खिलाफ मौत की सजा का फैसला किया

गया था जिन्होंने मातृभूमि को धोखा दिया, अपने लोगों को धोखा दिया और अपने उद्देश्य को धोखा दिया, और अपने ही लोगों को मारने के लिए कब्जा करने वालों के साथ हाथ मिलाया। बताया गया है कि तीनों लोगों को सिर पर और शरीर के ऊपरी हिस्से में गोलियां मारी गईं। इसके बाद उनके शव पर कुछ कागज चिपकाए गए, जिनमें अरबी में लिखा था, ÷तुम्हारा धोखा बिना सजा के नहीं होगा। एक कठोर सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमास के गृह मंत्रालय ने मारे गए तीनों लोगों पर इस्राइल से मिले होने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ इस्राइली अखबार इस्राइल हयोम ने कहा कि इस्लामिक जिहाद और मुजाहिदीन ब्रिगेड्स ने इस हत्या में भूमिका निभाई। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब हमास ने फलस्तीन के ही नागरिकों के खिलाफ बर्बरता की है। इससे पहले मई में भी हमास के लड़ाकों ने छह फलस्तीनियों को सरेआम मौत की सजा दी थी। इन पर तब मानवीय सहायता के तौर पर भेजे गए सामान की लूट का आरोप लगा था। 13 अन्य लोगों को उनके पैर पर गोली मारकर सजा दी गई थी।

जीएसटी कम होने का असर : विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की रेट में पंद्रह से बीस रुपए की कमी

एजेंसी

बीकानेर। केंद्र सरकार ने भुजिया पर लगे जीएसटी (गुड्स सर्विस टैक्स) को 12 परसेंट से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। ऐसे में भुजिया की रेट में पंद्रह से बीस रुपए की कमी आई है। बीकाजी समेत बीकानेर के भुजिया व्यापारियों ने दाम किए है। शहर में करीब 100 से ज्यादा भुजिया बनाने की भट्टियां हैं। इससे पहले भुजिया 220 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही थी। लेकिन, जीएसटी कम होने के बाद 15 से 20 रुपए कम हुए है। अब इसकी कीमत 200 रुपए प्रतिकिलो से शुरू हो रही है। बीकाजी ने दो सौ ग्राम पैकिंग वाला भुजिया की रेट 58 रुपए कर दी है, जबकि पहले इसकी रेट 62 रुपए थी। इसी तरह चार सौ ग्राम वाले पैकेट की रेट 122 रुपए से घटाकर 110 रुपए कर दी है। वहीं बीकाजी ने अपने गिफ्ट पैक भी सस्ते किए हैं, जिसमें भुजिया की पैकिंग शामिल है। इसमें 370 रुपए वाला पैकेट अब 350 रुपए में मिलेगा। वहीं 663 रुपए वाला पैकेट अब 630 रुपए में मिल सकेगा। दरअसल, इसमें मिठाई का पैकेट भी होता है, मिठाई पर जीएसटी में कोई अंतर नहीं आया है। बीकानेर की एक अन्य बड़ी भुजिया निर्माता कंपनी भीखाराम चांदमल ने जीएसटी धमाका नाम दिया है। कंपनी के प्रचार प्रसार से जुड़े ज्ञान गोस्वामी ने बताया कि 240 रुपए प्रति किलो भुजिया की रेट घटाकर अब 224 रुपए कर दी है। भुजिया के अन्य प्रोड्क्ट्स पर भी इसी अनुपात में रेट कम की गई है।

जीएसटी में नई कटौती से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी : जोशी

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने प्रह्लाद जोशी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती से 2030 तक निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी। साथ ही 2030 तक भारत के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के छठे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के अवसर पर जीएसटी दरों में की गई कटौती लागू होने के पहले दिन यह बात कही। सम्मेलन से इतर जोशी ने पत्रकारों से कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नवरात्रि के अवसर पर नवीकरणीय उपकरणों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा का लाभ मिला है।

कुरकुरे ने पूरे किए 25 साल, ज्वार पफ्स लॉन्च करके मिलेट बेस्ड स्नैकिंग में रखा कदम

नई दिल्ली। पेप्सिको इंडिया का मशहूर देसी स्नैक ब्रांड कुरकुरे अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस खास अवसर पर पेप्सिको ने मोटे अनाज से बने 'स्नैक' की श्रेणी में प्रवेश किया है। ये नया स्नैक फ्राइड नहीं, बल्कि बेक्ड है। कंपनी ने 'कुरकुरे ज्वार पफ्स' लॉन्च किए। पेप्सिको ने जारी बयान में कहा कि 'कुरकुरे ज्वार पफ' के साथ पेप्सिको दैनिक उपभोग की वस्तुएं बनाने वाली उन अन्य कंपनियों में शामिल हो गया है, जो देश में मोटा अनाज आधारित स्नैक की श्रेणी में कदम रख चुकी हैं। कुरकुरे ज्वार पफ्स को मॉडर्न एवं ट्रेडिशनल रिटेल, अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और क्विक कॉमर्स एप्स के माध्यम से उत्तर, पश्चिम एवं पूर्वी भारत में 10 रुपये और 20 रुपये के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। ये बदलाव मोटे अनाज की बढ़ती मांग के अनुरूप है, जिससे पेप्सिको इंडिया के लिए आज की पीढ़ी के लिए इस अनाज को फिर से पेश करने का अवसर मिला है। कुरकुरे ज्वार पफ्स से लोगों को अपने पसंदीदा इन्ग्रेडिएंट्स का मॉडर्न फॉर्मेट में आनंद लेने का मजेदार और स्वाद से भरपूर मौका मिलेगा। कंपनी के विपणन निदेशक (कुर्कुर एवं डोरिटोस) आस्था भसीन ने जारी बयान में कहा कि 'कुरकुरे ज्वार पफ' के साथ इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अनाज को एक सुलभ एवं अनूठा रूप से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही कुरकुरे ने बेहतरीन स्वाद और एक्साइटमेंट की पावर को साथ लाते हुए भारत की मिलेट-बेस्ड (मोटे अनाज आधारित) स्नैकिंग कैटेगरी में कदम रख दिया है।

सर्राफा बाजार में मजबूती के नए शिखर पर पहुंचा सोना, चांदी भी ऑल टाइम हाई पर

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। कीमत में उछाल आने के कारण सोना और चांदी दोनों चमकीली धातु अभी तक के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई हैं। कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,12,580 रुपये से लेकर 1,12,730 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,03,200 रुपये से लेकर 1,03,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी आज 5 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक का उछाल आया है। इस तेजी के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,38,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,12,730 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,03,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,12,580 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,03,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में इनविट्स बने नई ताकत

एजेंसी

जयपुर। भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को विकास की रीढ़ माना जा रहा है। देश में सड़कें, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइंस जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। इस दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी इनविट्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये न केवल डेवलपर्स के लिए पूंजी जुटाने का साधन हैं, बल्कि आम निवेशकों को भी देश के निर्माण कार्यों से सीधे तौर पर जोड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत 27 इनविट्स करीब सात लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर रहे हैं। आकलन है कि 2030 तक यह आकार तीन गुना होकर इक्कीस लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि इनविट्स निवेशकों को एक पारदर्शी और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, जहां से वे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का हिस्सा बन सकते हैं और नियमित रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। इनविट्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें निवेशक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध यूनिट्स के जरिए सिर्फ एक यूनिट खरीदकर भी निवेश कर सकता है। इस तरह छोटे निवेशक भी इस बड़े क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इनविट्स को अनिवार्य रूप से अपनी परिसंपत्तियों का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा आय उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में लगाना होता है और इन्हें अपनी शुद्ध वितरित योग्य नकदी का कम से कम 90 प्रतिशत

निवेशकों को लौटाना अनिवार्य है। यह भुगतान सामान्यत- तिमाही या अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही, 70 प्रतिशत तक का लीवरेज कैप और क्रेडिट रेटिंग जैसी शर्तें निवेशकों का विश्वास बढ़ाती हैं। यही कारण है कि इन्हें स्थिरता और तरलता का अनोखा संयोजन माना जाता है। दरअसल, इनविट्स को केवल निवेश का साधन मानना उचित नहीं होगा। ये एक नीतिगत नवाचार भी हैं, जो मौजूदा और पहले से चल रही परियोजनाओं को लाभकारी बनाकर पूंजी को नए प्रोजेक्ट्स में लगाने का अवसर देते हैं। यह मॉडल सरकार की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मानेटाइजेशन प्लान का महत्वपूर्ण आधार है। इन योजनाओं के जरिये केंद्र सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में खरबों रुपये का निवेश आकर्षित करना चाहती है। भारत में इनविट्स की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है इंडीग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। यह देश का पहला और सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पावर सेक्टर इनविट है, जिसे वैश्विक निवेश कंपनी केकेआर का समर्थन प्राप्त है।

आचार्य बालकृष्ण विश्व रैंकिंग के शीर्ष 2 फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में पुनः शामिल

एजेंसी

हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री व आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण को अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध समूह और विश्वप्रसिद्ध प्रकाशक एल्सेवियर के जारी विश्व के शीर्ष 2 फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में पुनः शामिल किया गया है। बाबा रामदेव ने इस उपलब्धि को पतंजलि, आयुर्वेद एवं भारत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण बताया। आचार्य बालकृष्ण के मार्गदर्शन से 300 से अधिक शोध लेखों का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स में किया गया है। उनके निर्देशन में पतंजलि ने 100 से अधिक साक्ष्य-आधारित आयुर्वेदिक औषधियों को विकसित किया गया है। योग और आयुर्वेद पर 120 से अधिक पुस्तकों और 25 से अधिक अप्रकाशित प्राचीन आयुर्वेद पांडुलिपियों का लेखन उनके आयुर्वेद के प्रति आस्था एवं समर्पण का परिणाम है। इस उपलब्धि पर स्वामी रामदेव ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण ने न केवल आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ स्थापित किया है, बल्कि विश्वभर के शोधकर्ताओं के लिए आयुर्वेद में शोध के नए द्वार भी खोले हैं। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में सम्मिलित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और सनातन आयुर्वेदिक ज्ञान में अपार संभावनाएं छिपी हैं। स्वामी जी ने इसे भारत की अनुसंधान क्षमता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत के सनातन ज्ञान को साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धरातल पर प्रमाणित कर महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके द्वारा किए गए शोध कार्य, विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से जुड़ें भविष्य के शोध कार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण पहुंचीं स्टेशनरी की दुकान, लिया जीएसटी के 'क्रियान्वयन' का जायजा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के क्रियान्वयन का राजधानी नई दिल्ली के कई इलाकों का भ्रमण करके जायजा लिया। सीतारमण ने इसी कड़ी में लक्ष्मी नगर में एक स्टेशनरी एवं किराना की दुकान पर पहुंचकर देखा कि जीएसटी बचत उत्सव के तहत लागू सुधारों का आम लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने नवरात्रि के पहले दिन अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन के बाद नई दिल्ली के सुभाष चौक और लक्ष्मी नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने इस मुलाकरत के दौरान दुकानदारों और उपभोक्ताओं का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की। सीतारमण ने जीएसटी सुधारों पर शुरुआती प्रतिक्रियाओं का जायजा लेने के लिए

स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। वित्त मंत्री ने इस दौरान सभी को भारत में निर्मित स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं के जवाब देते हुए कहा, प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। इस अवसर पर सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग तथा कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और लक्ष?मी नगर के विधायक अभय वर्मा भी उपस्थित थे।

देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 6.3 फीसदी बढ़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 6.3 फीसदी बढ़ा है। यह इसका 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पिछले महीने जुलाई में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.7 फीसदी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस्पात, कोयला, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि के कारण देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 6.3 फीसदी बढ़ा है। पिछले महीने जुलाई में इनका उत्पादन वृद्धि दर 3.7 फीसदी थी। पिछले साल अगस्त में यह माइनस 1.5 फीसदी थी। इससे पहले जुलाई, 2024 में 6.3 फीसदी की समान वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगस्त, 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में कोयला के उत्पादन में 11.4 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है। मंत्रालय के मुताबिक पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में अगस्त में 3.0 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। उर्वरक उत्पादन में 4.6 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि इस्पात

उत्पादन में सबसे तेज 14.2 फीसदी बढ़ा है। इसी तरह सीमेंट उत्पादन में 6.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। बिजली उत्पादन में 3.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन अगस्त में कच्चे तेल का उत्पादन 1.2 फीसदी और प्राकृतिक गैस का उत्पादन सालाना आधार पर 2.2 फीसदी घटा है। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-अगस्त के दौरान देश के आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन में 2.8 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इसमें 4.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई थी। देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। इन कोर इंडस्ट्रीज का संयुक्त सूचकांक भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल भार का 40.27 फीसदी होता है।

सरकार पीएमयूवाई के तहत नवरात्रि पर देगी 2.5 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत नारी शक्ति को बड़ा उपहार देने का ऐलान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के 25 लाख मुफ्त कनेक्शन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, 'उज्ज्वला परिवार का विस्तार नारी शक्ति को बड़ा उपहार! नवरात्रि के शुभारम्भ के साथ ही मुफ्त 25 लाख नए पीएमयूवाई कनेक्शन की सौगात एक और प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं को देवी दुर्गा जी के सामान सम्मान देते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने आगे लिखा है यह निर्णय माताओं-बहनों के सम्मान और

सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। मंत्री ने कहा, 'भारत सरकार प्रत्येक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी, जिससे लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा एवं रेगुलेटर आदि और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।' अब उज्ज्वला परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़कर 10.60 करोड़ हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इसे महिलाओं के लिए नवरात्रि का तोहफा बताते हुए कहा कि उज्ज्वला का विस्तार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नारी शक्ति के सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुरी ने आगे लिखा है धरती पर नारी रूप में देवी मां की शक्ति विचरती है। भारतीय संस्कृति में भी नारी को 'शक्ति' का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में हम मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करते हैं, जो नारी शक्ति का प्रतीक हैं। यही भाव मोदी जी की नीयत एवं योजनाओं में भी साफ झलकता है। भारत में सबसे प्रभावशाली सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनकर उभरी उज्ज्वला योजना नारी सम्मान और सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उज्ज्वला योजना ने सिर्फ रसोई ही नहीं उज्जवल की, उस पूरे परिवार का, माताओं बहनों का भविष्य भी उज्जवल किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ योजना मात्र नहीं देश में बहुत बड़ी क्रांति की मशाल बनी है, जिसकी लौ देश के कोने-कोने में, सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंची है। वर्तमान में मोदी सरकार की 300 रुपये की सब्सिडी के साथ 10.33 करोड़+ उज्ज्वला परिवारों का सिलेंडर केवल 553 रुपये में रिफिल हो जाता है। यह कीमत दुनियाभर के एलपीजी उत्पादक देशों से भी कम है।

हरित भारत रिन्यूएबल एनर्जी एवं ईवी एक्सपो -2025 : जोधपुर बनेगा ग्रीन एनर्जी और ई-मोबिलिटी का हब

एजेंसी

जोधपुर। मिशन हरित भारत के तहत लघु उद्योग भारती, सोलर संगठन भारत, जोधपुर सोलर सोसायटी और टीम हरित भारत के संयुक्त तत्वावधान में हरित भारत रिन्यूएबल एनर्जी एवं ईवी एक्सपो -2025 का भव्य आयोजन 21 से 23 नवम्बर तक गांधी मैदान में किया जाएगा। यह एक्सपो राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है।

यह होगी इस एक्सपो की खासियतः

सोलर संगठन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंधवा ने बताया कि तीन दिवसीय इस आयोजन में देशभर की 100 से अधिक अग्रणी कंपनियाँ भाग लेंगी। इसमें सोलर इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, ईवी निर्माता कंपनियाँ, बैट्री, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर एवं मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ और सहायक कम्पोनेंट उद्योग शामिल होंगे। जोधपुर सोलर समिति के संरक्षक रामचंद्र ने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित इसी आयोजन में लगभग 20 हजार विजिटर्स पहुँचे थे और करीब 10 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए थे। इस आयोजन ने जोधपुर को ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर का उभरता केंद्र साबित किया था। सोलर संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक अरोड़ा ने बताया कि यह एक्सपो प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना और देश की ई-मोबिलिटी नीति को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनेगा। आयोजन से युवाओं को रोजगार व स्टार्टअप के नए अवसर मिलेंगे, राजस्थान का सोलर हब के रूप में दबदबा और मजबूत होगा तथा ईवी सेक्टर में निर्माण व सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा।

डॉलर की तुलना में 22 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया

एजेंसी

नई दिल्ली। कमजोर ग्लोबल संकेतों, स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और डॉलर की मांग में तेजी आने का असर आज भारत के मुद्रा बाजार में साफ-साफ नजर आया। मुद्रा बाजार में बने नकारात्मक माहौल के कारण रुपया आज डॉलर की तुलना में कमजोर होकर बंद हुआ। भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 22 पैसे फिसल कर 88.32 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा 88.10 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की कमजोरी के साथ 88.18 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के बाद कुछ देर के लिए रुपया ओपनिंग लेवल से 7 पैसे की रिकवरी करके 88.11 के स्तर तक भी पहुंचा, लेकिन इसके

बाद बाजार में बने नकारात्मक माहौल के कारण रुपया 25 पैसे की कमजोरी के साथ 88.35 के स्तर तक पहुंच गया। पूरे दिन के कारोबार के बाद डॉलर की तुलना में रुपये ने 22 पैसे की गिरावट के साथ 88.32 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। मुद्रा बाजार के आज के कारोबार में रुपये ने डॉलर के साथ ही ज्यादातर दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले भी कमजोर प्रदर्शन किया। आज के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया 26.42 पैसे की कमजोरी के साथ 119.23 (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह यूरो की तुलना में रुपया आज 38.68 पैसे की गिरावट के साथ 103.99 (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच कर बंद हुआ। खुराना सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ रवि चंदर खुराना के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी हलचल और अमेरिका द्वारा अपने मन के मुताबिक ट्रेड डील करने की कोशिश में भारत पर लगातार बढ़ाए जा रहे दबावों की वजह से विदेशी निवेशक लगातार भारत से अपने पैसे की निकासी करने में लगे हुए हैं। इसकी वजह से मुद्रा बाजार में डॉलर तथा दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की मांग में तेजी का रुख बना हुआ है।

पेस डिजिटेक लिमिटेड का आईपीओ 26 सितंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 208-219 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली। दूरसंचार समाधान प्रदाता कंपनी पेस डिजिटेक लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 26 सितंबर को खुलेगा। इसमें निवेशक 30 सितंबर तक बोली लगा सकते हैं। इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 208-219 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। पेस डिजिटेक लिमिटेड के मुताबिक उसका आईपीओ 26 सितंबर को खुलकर 30 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस इश?यू के लिए मूल?य का दायरा 208-219 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ये आईपीओ एक नया इश्यू है, जिसका कुल मूल्य 819.14 करोड़ रुपये है। निवेशक इसमें न्यूनतम 68 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 68 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। निर्गम का कुल आकार 819.15 करोड़ रुपये का है, जिसमें 3,74,04,018 नए शेयर शामिल हैं। इस इश्यू में बिक्री के

लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) शामिल नहीं है। पेस डिजिटेक लिमिटेड नए निर्गम से प्राप्त 630 करोड़ रुपये की राशि कंपनी की सहायक कंपनी पेस रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय की ओर निर्देशित के लिए करेगी, ताकि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ एक परियोजना के बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जा सके, जबकि शेष धनराशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए जाएगी।

टूअल्ट बायोएनर्जी का आईपीओ 25 सितंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 472-496 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली। जैव ईंधन बनाने वाली कंपनी टूअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 25 सितंबर को खुलेगा। इसमें निवेश करने के लिए निवेशक 29 सितंबर तक बोली लगा सकते हैं। इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 472-496 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। टूअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड ने सोमवार को एक बयान में बताया कि उसका आईपीओ 25 सितंबर को खुलकर सोमवार, 29 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने 10 अंकित मूल्य वाले इस इश्यू के लिए मूल्य का दायरा 472-496 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के मुताबिक यह आईपीओ 750 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर और प्रवर्तकों द्वारा 89.28 करोड़ रुपये मूल्य के 18 लाख शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। इस प्रकार इस निर्गम का कुल आकार 839.38 करोड़ रुपये बैठता है। निवेशक इसमें निवेश के लिए न्यूनतम 30 इक्विटी शेयर और उसके बाद 30 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। जैव ईंधन बनाने वाली कंपनी टूअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड नए निर्गम से प्राप्त 150.68 करोड़ रुपये की राशि से 300 किलो लीटर प्रतिदिन (केएलपीडी) क्षमता वाले टीबीएल यूनिट 4 में इथेनॉल संयंत्र में अतिरिक्त कच्चे माल के रूप में अनाज के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने हेतु बहु-फ़ीड स्टॉक परिचालन स्थापित करने हेतु पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण के लिए करेगी।

सप्ताह के पहले दिन ही गिरा शेयर बाजार, आईटी सेक्टर में बिकवाली से बिगड़ा मूड

एजेंसी

नई दिल्ली। आईटी सेक्टर के शेयरों की जम कर हुई बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार का मूड लगातार बिगड़ा रहा। आईटी सेक्टर पर पड़े दबाव का असर आज शेयर बाजार के कारोबार पर साफ-साफ नजर आया। इस दबाव के कारण सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद पहले आधे घंटे के कारोबार में खरीदारी के सपोर्ट से दोनों सूचकांक काफी हद तक रिकवरी करने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद पूरे दिन बाजार पर बिकवाली का दबाव बना रहा। खासकर दोपहर 2 बजे के बाद चौतरफा बिकवाली शुरू हो जाने के कारण इन दोनों सूचकांकों में तेज गिरावट आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.56 प्रतिशत और निफ्टी 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान आईटी सेक्टर के अलावा डिफेंस, फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी सेक्टर में भी जम कर बिकवाली होती रही। इसी तरह रियल्टी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। दूसरी ओर ऑयल एंड गैस, मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में आज खरीदारी होती रही। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब सवा लाख करोड़ रुपये की कमी आ गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 465.08 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 466.32 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 1.24 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,455 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,778 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,507 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 170 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,817 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,080 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,737 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 9 शेयर बढ़त के साथ और 21 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान में और 29 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 545.16 अंक की गिरावट के साथ 82,151.07 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे इस सूचकांक की चाल में सुधार होने लगा। लगातार हो रही खरीदारी के कारण पहले आधे घंटे के कारोबार में ही सेंसेक्स ओपनिंग लेवल से 500 अंक से अधिक की रिकवरी करके 82,583.16 अंक के स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद बाजार पर बिकवालों ने अपना दबाव बना दिया, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में गिरावट आने लगी। खासकर दोपहर 2 बजे के बाद बिकवाली तेज हो जाने के कारण आधे घंटे के कारोबार में ही ये सूचकांक 628.94 अंक लुढ़क कर 81,997.29 अंक तक गिर गया। हालांकि इसके बाद खरीदारों ने एक बार फिर मोर्चा संभाला, जिसके कारण सेंसेक्स निचले स्तर से 160 अंक से अधिक की रिकवरी करके 466.26 अंक की कमजोरी के साथ 82,159.97 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

घर की दहलीज से सुप्रीम कोर्ट तक... शाह बानो के किरदार में

यामी गौतम

का फर्स्ट लुक आया, इस दिन जारी होगा टीजर

इमरान हाशमी और यामी गौतम पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने जा रहे हैं. उस पिक्चर का नाम है 'हक'. शाह बानो और मोहम्मद अहमद खान केस पर प्रेरित इस फिल्म को सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया है. अब इस फिल्म से यामी का एक पोस्टर सामने आया है. साथ ही टीजर रिलीज डेट भी बता दी गई है.मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म से यामी का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. यामी हाथों में फाइल लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती दिख रही हैं. पोस्टर पर फिल्म के टाइटल के साथ-साथ ये भी लिखा है, कौन दिलाएगा हक, कौम या कानून ? मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए ये भी लिखा, घर की दहलीज से सुप्रीम कोर्ट तक, हक की लड़ाई.

इस दिन आएगा टीजर

इस फिल्म में यामी गौतम शाह बानो के रोल में नजर आने वाली हैं. इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान के किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म का टीजर 23 सितंबर को जारी होगा. मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो को तीन तलाक दे दिया था और उन्हें छोड़ दिया था. साथ ही अहमद ने गुजारा भत्ता देने से भी मना कर दिया था.

उसके बाद शाह बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने हक की लड़ाई लड़ी थी. कोर्ट का फैसला उनके हक में आया था.अब उसी मामले को डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा पर्दे पर पेश करने वाले हैं. अभी इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. यामी का जो फर्स्ट लुक पोस्टर आया है उसमें वो शाह बानो के रोल में जच रही हैं.

यामी गौतम और इमरान हाशमी का वर्कफ्रंट

यामी आखिरी बार इसी साल फरवरी में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'धूम धाम' में दिखी हैं. वहीं इमरान इसी साल अप्रैल में 'ग्राउंड जीरो' में दिखे हैं. ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी. इसके अलावा उन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो भी किया है. इस सीरीज को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है.

रेत के तूफानों के बीच सलमान खान ने की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग,

चित्रांगदा सिंह

ने क्या बताया?

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी अगली फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्म का नाम है 'बैटल ऑफ गलवान', जिसे अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की काफी समय से चर्चा हो रही है. सलमान इस फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख गए थे. कुछ दिन पहले ही वो वहां से शूटिंग करके लौटे हैं. शूटिंग के दौरान उन्हें रेत का तूफानों का सामना

करना पड़ा.इस फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं. वो भी लद्दाख से शूटिंग करके लौट चुकी हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान चित्रांगदा ने अपना शूटिंग एक्सपीरियंस बताया है. उन्होंने कहा, बहुत एक्साइटिंग था. ये पहली बार है जब मैं सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूं. मैं उन्हें जानती हूं, लेकिन प्रोफेशनल तौर पर सेट पर होना बहुत अलग और रोमांचक है.

एक्शन सीन की शूटिंग में दिक्कत

चित्रांगदा सिंह ने आगे कहा, लद्दाख में शूटिंग करके मजा आया, लेकिन हमलोगों को रेत के तूफानों का सामना करना पड़ा. सलमान के लिए एक्शन सीन शूट करना मुश्किल था. और मैं वहां बैठी थी. चित्रांगदा ने नीरज घायवान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'होमबाउंड' के भारत की तरफ ऑस्कर के लिए ऑफिशियली एंट्री के तौर पर चुने जाने पर भी रिएक्ट किया है.

'होमबाउंड' के ऑस्कर के लिए चुने जाने पर क्या बोलीं चित्रांगदा ?

उन्होंने कहा, ये हमारे लिए गर्व की बात है. जो भारत से आ रहा है वो पश्चिमी दुनिया के अंग्रेजी बोलने वाले माध्यम की तुलना में शानदार है. हमारा काम उतना ही अच्छा है. बहरहाल, सलमान और चित्रांगदा की 'बैटल ऑफ गलवान' साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है. उसी झड़प में कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए थे. सलमान उनके रोल में ही नजर आने वाले हैं. साल 2026 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है.इस फिल्म के अलावा सलमान इन दिनों टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में भी बिजी चल रहे हैं. जब वो 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग को लेकर लद्दाख गए थे तो उनकी गैर-मौजूदगी में फराह खान ने उनके इस शो के 'वीकेंड का वार' होस्ट किया था.

एंटरटेनमेंट और नीचे गिरने में फर्क है... 'बिग बॉस 19' देख अमाल मलिक पर भड़कीं आवेज की भाभी गौहर खान

सलमान खान के टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में कंटेस्टेंट के बीच खूब लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं. सिंगर अमाल मलिक और कोरियाग्राफर आवेज दरबार के बीच भी कई बार शो में झगड़े देखने को मिले हैं. शो में कंटेस्टेंट कई बार एक दूसरे के लिए गालियों का भी इस्तेमाल कर देते हैं. इसी चीज को लेकर अब आवेज की भाभी और टीवी एक्ट्रेस गौहर खान अमाल पर भड़की नजर आई हैं.गौहर खान 'बिग बॉस 7' की विनर रह चुकी हैं. उनका कहना है कि इस शो से उन्हें काफी लगाव है और वो ये शो देखती हैं. हालांकि, 'बिग बॉस 19' पर उनका और भी ज्यादा फोकस है, क्योंकि उनके देवर आवेज इस शो में हैं. इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गौहर ने लिखा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो बोल देनी चाहिए अगर आपके दिल और दिमाग में है तो. मैं कोशिश करती हूं कि ज्यादा शामिल नहीं हूं और ज्यादा न बोलूं. आवेज 'बिग बॉस' में है और बिग बॉस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो 90 प्रतिशत समय आपको नजरअंदाज करना होता है अगर आपका कोई उस शो में है तो. मैं 'बिग बॉस' की बहुत बड़ी फैन हूं. मैं ये शो तो वैसे भी देखती हूं. उसमें मेरा कोई अपना हो या न हो.

गौहर खान ने अमाल को क्या कहा ?

गौहर ने आगे कहा, मैं आपको बताना चाहती हूं अमाल कि आप शो के अंदर हैं और आप काफी अच्छा कर रहे हैं. मुझे भी पसंद आ रहे हैं आप, क्योंकि आप एंटरटेनिंग हैं. लेकिन एंटरटेनमेंट में और नीचे गिरने में बहुत ज्यादा फर्क है. आप लोगों के पीठ पीछे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं. बात तो कर रहे हैं कोई बात नहीं है, बात तो होती है 'बिग बॉस' में, प्लीज करिए. लेकिन आप जो गालियां दे रही हैं वो बहुत शर्मनाक है.

प्रणित मोरे और गौरव खन्ना का जिक्र

वो आगे बोलीं, अमाल इतनी सारी गालियां आसानी से बोल देते हैं. उन्होंने प्रणित को जेबरा बुलाया. जातिवादी टिप्पणी. ये तो हर कोई जानता है कि वो तो उनके हाइट के बारे में बात नहीं कर रहे थे. वो उनके रंग के बारे में बात कर रहे थे. अमाल ने कहा गौरव के बारे में कि छोड़ उसको बाहर जाकर टीवी सीरियल बनाओ. टीवी सीरियल बनाना क्या कोई छोटी बात होती है. करोड़ों रुपये लगते हैं उसमें. टीवी एक्टर्स कई फिल्म स्टार्स से भी बड़े होते हैं. आप उनके फेम को छू भी नहीं पाओगे.

खेसारी के साथ डांस करते करते पूल में गिरे वरुण धवन, भोजपुरी स्टार ने भी लगा दी छलांग

2024 में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के दो हिंदी गाने 'आई नहीं' और 'चुम्मा' आया था जिसने लोगों को खूब एंटरटेन किया. वहीं 2025 में भोजपुरी ट्रेंडिग स्टार खेसारी लाल यादव का हिंदी गाना 'पनवाड़ी' आया और इसी से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई. 'पनवाड़ी' गाना वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की आने वाली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का है. ये गाना कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, इसपर आज वरुण धवन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो खेसारी के साथ स्विमिंग पूल के पास डांस करते नजर आ रहे हैं.वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर खेसारी के साथ वाला वीडियो शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'कौन जानता था कि पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में स्विमिंग पूल होगा. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और भोजपुरी समाज को नमस्कार.' इस वीडियो में वरुण और खेसारी फनी अंदाज में स्विमिंग पूल के पास डांस करते नजर आ रहे हैं जो देखने में काफी मजेदार है.

इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करण जौहर ने ढेर सारे फनी और हार्ट इमोजी भेजे हैं और करण इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं. वहीं मनीष पॉल ने कमेंट में लिखा है, 'हा हा हा लव यू दोस्तों वरुण और खेसारी.' वहीं दूसरे लोगों ने भी कमेंट किया है. किसी ने लिखा कि ऐसा कोलैब होगा सोचा भी नहीं था. वहीं खेसारी के एक फैन ने लिखा, 'खेसारी भइया जियो, छा गए.' वरुण और खेसारी के इस वीडियो पर खेसारी के फैंस काफी खुश हैं.

किसने बनाई है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ?

'पनवाड़ी' गाना 10 सितंबर को रिलीज हुआ था जिसे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल और हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने गाया है. ये गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वहीं फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के डायरेक्टर शशांक खैतान हैं. शशांक के साथ वरुण धवन 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं.

फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में वरुण के अपोजिट जाह्नवी कपूर हैं, वहीं मनीष पॉल, रोहित सुरेश सराफ और सान्या मल्होत्रा जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

Avonleigh University के एशिया फ्रेंचाइजी ऑफिस का पश्चिम विहार, दिल्ली में हुआ उद्घाटन

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। दिल्ली के पश्चिम विहार में **Avonleigh University** के एशिया फ्रेंचाइजी ऑफिस का भव्य उद्घाटन किया गया। शुभारंभ हवन के आयोजन के साथ हुआ, जिसमें कई गणमान्य हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी की बोर्ड मेंबर भावना धवन, यूनिवर्सिटी से विशाल कश्यप और शिवानी कौर, सीए रवि सेठी, नेशनल अकाली दल के परमजीत सिंह पम्मा, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अनिल कुमार कथुरिया, एडवोकेट मोहित भारद्वाज, समाजसेवी शालू दुग्गल, जयवीर नान एंड चाप के मालिक जयवीर यादव व प्रदीप यादव, समाजसेवी अजय शर्मा, तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक अजय भाटिया, समाजसेवी अनिल कुमार, सोनू अग्रवाल, सिंगर गुलशन सुमन, नंद किशोर, योगेश धिमान, जयपुर से टी. सी. शर्मा एडवोकेट करमवीर और हरीश बब्बर सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि मौजूद रहे। सभी का गरिमामय स्वागत किया गया। **Avonleigh University** का उद्देश्य दुनिया भर के शिक्षार्थियों को सुलभ, किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। यह संस्था शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से छात्र अमेरिका-मान्यता प्राप्त और विश्व स्तर पर स्वीकार्य प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा 50 से अधिक देशों के विविध नेटवर्क से जुड़ने का अवसर पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के जरिए **Avonleigh University** वैश्विक स्तर पर छात्रों को नई दिशा और अवसर प्रदान कर रही है।

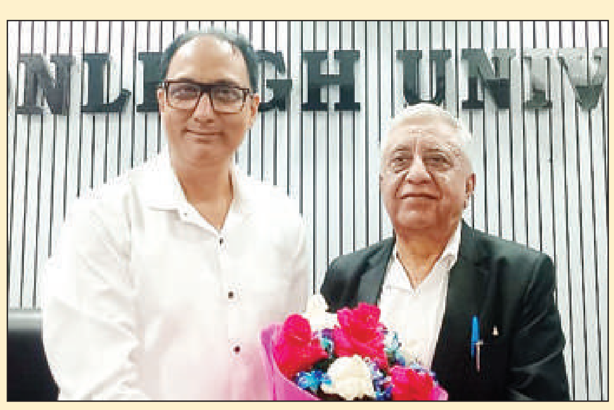

पूनम पांडे अब नहीं निभाएंगी मंदोदरी की भूमिका, लव कुश रामलीला समिति का बड़ा फैसला

दिव्य दिल्ली : लालकिला मैदान में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में इस बार अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका नहीं निभाएंगी। समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों से आई आपत्तियों के बाद यह निर्णय लिया है।समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि पूनम पांडे ने समिति के आमंत्रण पर मंदोदरी की भूमिका निभाने की सहमति दी थी। लेकिन उनके नाम की घोषणा के बाद अनेक संस्थानों और वर्गों से आपत्तियाँ सामने आईं, जिससे रामलीला के उद्देश्य–प्रभु श्रीराम का संदेश समाज तक पहुँचाना–में बाधा उत्पन्न हो रही थी।गहन विचार-विमर्श के बाद समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि इस वर्ष मंदोदरी की भूमिका किसी अन्य कलाकार से करवाई जाएगी। समिति ने पूनम पांडे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे इस निर्णय को समझेंगी और क्षमा करेंगी।

पूर्वजों की स्मृति एवं प्रकृति के प्रति आस्था का लोक पर्व बुन्देलखण्ड का महाबुलिया

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर में कई प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित हैं। इन्हीं में से एक है महाबुलिया पर्व, जिसकी जड़ें द्वापर युग तक जाती हैं। मान्यता है कि इस लोक परंपरा की शुरूआत स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने की थी। कथाओं के अनुसार, द्वापर काल में कृष्ण ने लड़कियों से कहा था कि वे अपने पूर्वजों के तर्पण और स्मरण हेतु विशेष अनुष्ठान करें। तभी से यह परंपरा शुरू हुई।

पुणे में जीआईबीएफ ने किया भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का भव्य आयोजन

विनय आजादपुर

दिव्य दिल्ली : पुणे। भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का तीसरा संस्करण पुणे के ग्रैंड हेरिटेज रिसॉर्ट्स में आयोजित किया गया। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम (जीआईबीएफ) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं का अवसर मिला।

सम्मेलन में 800 से अधिक भारतीय कंपनियाँ और अफ्रीकी महाद्वीप के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि एक साथ आए जिससे व्यापार,निवेश और साझेदारी के नए अवसर खुले। इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि डॉ.कांगो की शिक्षा मंत्री महामहिम जीनोट कैन्ट लारोज उपस्थित रहीं।भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में बहुत सारी कंपनियों ने अफ़्रीकी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया जिसमें कृषि,खाद्य प्रसंस्करण,खनन सौर ऊर्जा और बहुत सारे एमओयू साइन हुए जिससे आने वाले समय में कई भारतीय कंपनियां अफ़्रीकी कंपनियों के साथ काम कर सकती हैं। जीआईबीएफ भारतीय एसएमई उद्यमियों के लिए बेहद ही सुनहरा अवसर उपलब्ध करा रहा है। जिसका महाराष्ट्र सरकार ने स्वागत किया है,इसके साथ ही पीएम मोदी का भारतीय उद्यमियों को लोकल से ग्लोबल बिजनेस का सपना साकार करने में जीआईबीएफ का अहम रोल होगा।

इस अवसर पर जीआईबीएफ के प्रेसिडेंट डॉ. जितेंद्र जोशी ने कहा, इस सम्मेलन ने भारत-अफ्रीका के बीच अवसरों का एक मजबूत पुल बनाया है। जीआईबीएफ की सेक्रेटरी जनरल दीपाली गडकरी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद किया। इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, नाइजीरिया, इथियोपिया, केन्या, नामीबिया, बोत्सवाना, कैमरून, कांगो, डॉ.कांगो, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, घाना, मिस्त्र, जाम्बिया, तंजानिया, युगांडा,रवांडा आदि जैसे 25 अफ्रीकी देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई, जिन्होंने अपने-अपने देशों में व्यापार और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया।

गुरैठा निवासी पेंटर योगेश का हत्यारोपित मनोज मुठभेड़ में गिरफ्तार

मुरादाबाद। जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव गुरैठा निवासी योगेश कुमार (22) के हत्यारोपित बदायूं निवासी मनोज से रविवार देर रात्रि में थाना पाकबड़ा पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित मनोज पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने आज बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार मनोज ने योगेश की हत्या करने के बाद मृतक के मोबाइल से डायल 112 पुलिस को योगेश बनकर काल की थी और अपनी प्रेमिका के परिजनों द्वारा पीटे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

थाना पाकबड़ा के गांव गुरैठा निवासी योगेश कुमार पुत्र जोगेंद्र पेंटर का काम करता था। परिवार में पिता जोगेंद्र दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में सफाईकर्मी है।

ऑयल इंडिया ने वित्त वर्ष 26 में 7.5 एमएमटी उत्पादन का लक्ष्य रखा, रिफाइनरी और गैस विस्तार योजनाओं को बढ़ावा दिया

दिव्य दिल्ली : 20 सितंबर, 2025 ऑयल इंडिया का लक्ष्य FY26 में रिकॉर्ड 7.5 एमएमटी उत्पादन का है, जो रिफाइनरी विस्तार, पेट्रोकेम निवेश और उच्च ड्रिलिंग गतिविधि द्वारा समर्थित है।ऑयल इंडिया, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, 2025-26 (वित्तीय वर्ष 26) के लिए मजबूत तैयारी कर रहा है, जिसमें 7.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तेल और तेल समकक्ष का उत्पादन करने की योजना है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रंजीत राठ ने कहा कि कंपनी बढ़ी हुई ड्रिलिंग और अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हम ड्रिलिंग की संख्या को बहुत अधिक बढ़ाने और अन्वेषण, औसत और भूकंपीय डेटा कवरेज को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं,ह्व उन्होंने सीएनबीसी टीवी18 को बताया। यह 2024-25 (वित्तीय वर्ष 25) के एक ऐतिहासिक वर्ष के बाद आ रहा है, जहां कंपनी ने 6.71 एमएमटी का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया, जो उसका अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तार निर्धारित समय के अनुसार प्रगति कर रहा है, जिसमें प्राथमिक इकाइयों का कमीशन दिसंबर 2025 तक अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 27 तक क्षमता उपयोग 40-50% तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, ऑयल इंडिया ने अपने पेट्रोकेमिकल्स पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए एक पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट स्थापित करने के लिए 7,000 करोड़ का निवेश करने का वचन दिया है। इस परियोजना के 2028-29 (वित्तीय वर्ष 29) तक पूरा होने की उम्मीद है, जो कंपनी के संचालन में दीर्घकालिक मूल्य जोड़ देगा। प्राकृतिक गैस के मोर्चे पर, ऑयल इंडिया अपनी निकासी क्षमता को 8 से 13 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। उत्तर पूर्व गैस ग्रिड से जुड़ाव 5-6 एमएमएससीएमडी की आपूर्ति को सक्षम करेगा, जो रिफाइनरी संचालन का भी समर्थन करेगा। अन्वेषण सेवाओं पर हालिया जीएसटी वृद्धि, जो 300-400 करोड़ जोड़ने का अनुमान है, कंपनी द्वारा प्रबंधनीय मानी जाती है और निवेश योजनाओं को पटरी से उतारने की उम्मीद नहीं है। राठ ने यह भी साझा किया कि ऑयल इंडिया बेहतर ड्रिलिंग दक्षता और तेज टर्नअराउंड समय के माध्यम से लागत अनुकूलन का पीछा कर रहा है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321